दैनिक

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से एक साथ प्रकाशित

RNI. No. 69062/94

निष्पक्ष एवं निर्भीक विचारों का समाचार पत्र

प्रभात परिक्रमा

वर्ष: 31 | अंक: 235 | भोपाल, सोमवार 7 सितंबर 2026 | पृष्ठ: 08 | मूल्य: 1 रुपए

आवश्यकता है

दैनिक प्रभात परिक्रमा समाचार पत्र को प्रदेश के सभी जिलों एवं तहसील स्तर पर संवाददाता एवं एजेंटों की आवश्यकता है

: संपर्क :

9425023929

मुख्यमंत्री डॉ. यादव दुबई में वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे मध्यप्रदेश की विकास और निवेश संभावनाएं

एआईएम कांग्रेस 2026 में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का करेंगे नेतृत्व

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 के लिए वैश्विक निवेशकों को आमंत्रित करने के साथ नई औद्योगिक साझेदारियों पर रहेगा विशेष फोकस

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार से 9 सितंबर 2026 तक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई यात्रा पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल एआईएम कांग्रेस-2026 में सहभागिता करेगा। मुख्यमंत्री की यह यात्रा मध्यप्रदेश के वैश्विक निवेश संपर्कों को सुदृढ़ करने, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के समक्ष राज्य की आर्थिक एवं औद्योगिक क्षमताओं को प्रस्तुत करने और नई निवेश साझेदारियों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित एआईएम कांग्रेस-2026 में मध्यप्रदेश की निवेश क्षमता, औद्योगिक आधार और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध निवेश अवसरों को वैश्विक उद्योग जगत के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यात्रा के दौरान ह्यइन्वेस्ट मध्यप्रदेश' विषय पर विशेष सत्र भी प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यमंत्री राज्य के निवेश-अनुकूल वातावरण और औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डालेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश भारत के तेजी से उभरते औद्योगिक और निवेश गंतव्यों में अपनी सशक्त पहचान बना रहा है। राज्य में उपलब्ध संसाधन, बेहतर आधारभूत संरचना, उद्योग-अनुकूल वातावरण और निवेशकों के लिए विकसित सुविधाएं प्रदेश को निवेश के लिए आकर्षक बनाती हैं। हमारा प्रयास है कि वैश्विक निवेशकों के साथ मजबूत साझेदारी स्थापित कर मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दुबई यात्रा मध्यप्रदेश और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक एवं औद्योगिक सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वैश्विक निवेशकों और उद्योग समूहों के साथ होने वाली बैठकें प्रदेश में नए निवेश और रोजगार के अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की यात्रा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जनवरी 2027 में भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क एवं सहभागिता को बढ़ावा देना भी है। यात्रा में संयुक्त अरब अमीरात सरकार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 में पार्टनर कंट्री के रूप में आमंत्रित करने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव एआईएम कांग्रेस के उद्घाटन समारोह, वैश्विक नेतृत्व से जुड़े कार्यक्रमों तथा विभिन्न निवेश और व्यावसायिक बैठकों में सहभागिता करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्यप्रदेश मंडप का अवलोकन भी करेंगे और वैश्विक कॉर्पोरेट समूहों के साथ वन-टू-वन बैठकों में मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। दुबई यात्रा के दौरान सरकारी एवं व्यावसायिक स्तर की बैठकों के साथ राष्ट्र प्रमुख और संस्थागत निवेशकों के साथ राउंड टेबल बैठक भी प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर हुए 3 अधिकारी निलंबित, 1 को किया मुख्यालय अटैच

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर जिले की बंडा तहसील के तीन गांवों में नकली शराब पीने से कुछ लोगों की मौतों के मामलों मे सख्त एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर आबकारी आयुक्त श्री दीपक सक्सेना ने तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जबकि एक अधिकारी को मुख्यालय अटैच किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रविवार, 6 सितंबर की सुबह ही स्पष्ट रूप से कह दिया था कि इस घटना के लिए दोषी किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। शराब के मामले में दुःखद घटना सागर जिले के बंडा तहसील के ग्राम गोगरा खुर्द, नौरोज, और पाटन में हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर आबकारी आयुक्त श्री दीपक सक्सेना ने प्रथम दृष्टया जिम्मेदार मानते हुए सागर की सहायक आबकारी आयुक्त कीर्ति दुबे, सहायक जिला आबकारी अधिकारी दिलीप खंडाते और बंडा वृत्त के आबकारी उप-निरीक्षक प्रोशनी उरेती को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में समान रूप से जिम्मेदार मानते हुए उपायुक्त एवं संभागीय फ्लाइंग स्क्वाड प्रभारी नीरजा श्रीवास्तव को जिले से हटाकर ग्वालियर मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिखाई सख्ती मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह संवेदनशील मामला है नई दिल्ली प्रवास के दौरान यह मामला संज्ञान में आते ही मैंने सागर जिले के प्रभारी मंत्री एवं संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्र में तत्काल जांच, राहत और उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सागर संभाग के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। अधिकारी दल ने प्रभावित परिजन से भी मुलाकात की थी। अधिकारी दल ने अस्पताल में भर्ती मरीजों के उपचार और चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और आवश्यक उपचार तत्काल करने के निर्देश दिये।

इसरो के निजीकरण पर बवाल

9 कर्मचारी संगठनों ने सरकार के फैसले पर उठाए सवाल, अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी

सरकार की तरफ से अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के करीब छह साल बाद अब इसरो के हजारों कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 संगठनों ने प्रस्तावित बदलावों को लेकर सवाल उठाए है।

नई दिल्ली। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से निजी कंपनियों के लिए खुल रहा है. लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के भीतर, कर्मचारियों का एक वर्ग एक सवाल उठा रहा है कि यह निजीकरण कितनी दूर तक जाएगा, और रॉकेट, उपग्रह निर्माण और प्रक्षेपण अवसंरचना के संचालन में इसरो की अपनी भूमिका का क्या होगा यह सवाल अब संगठन के शीर्ष स्तर तक पहुंच चुका है। सरकार की तरफ से अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के करीब छह साल बाद अब इसरो के हजारों कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 संगठनों ने प्रस्तावित बदलावों को लेकर सवाल उठाए हैं। इसरो के अलग-अलग केंद्रों से जुड़े 9 संगठनों ने अंतरिक्ष विभाग और इसरो प्रमुख से इस नीति पर आधिकारिक स्पष्टीकरण मांगा है. कर्मचारी संगठनों ने पूछा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ने के बाद इसरो की भविष्य की भूमिका क्या होगी और इसका मौजूदा कर्मचारियों एवं आने वाली भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा।

नौ कर्मचारी संगठनों ने लिखा पत्र

4 सितंबर को इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव वी. नारायणन को लिखे एक पत्र में इन कर्मचारी संगठनों ने सरकार की निजीकरण नीति, इसरो की भविष्य की भूमिका और सेवारत कर्मचारियों और भविष्य की भर्ती पर इसके परिणामों के बारे में स्पष्टता की मांग की। इस पत्र पर इसरो के कई केंद्रों के कर्मचारी संगठनों ने हस्ताक्षर किए हैं। कर्मचारी संगठनों ने कहा कि निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ावा देने को लेकर सार्वजनिक मंचों पर कई बयान सामने आए हैं, लेकिन अंतरिक्ष विभाग की तरफ से कर्मचारियों को अब तक कोई स्पष्ट आधिकारिक नीति नहीं बताई गई है। पीएसएलवी और एलवीएमएक्स भी निजी क्षेत्र को देने की चर्चा कर्मचारी संगठनों की चिंता उस बयान के बाद बढ़ी है जब हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र के चेयरमैन पवन कुमार गोयनका ने एक कार्यक्रम में कहा था कि इसरो कोई भी प्रक्षेपण यान नहीं बनाएगा।

सैटेलाइट निर्माण और लॉन्च सुविधाओं को लेकर सवाल

कर्मचारी संगठनों ने इसरो में होने वाले नियमित सैटेलाइट निर्माण को भी बाहर ले जाने की खबरों पर चिंता जताई है। इसके अलावा कुलसेकरपट्टिनम में बन रहे स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स जैसी नई लॉन्च सुविधाओं को निजी कंपनियों के लिए खोलने की संभावनाओं पर भी सवाल उठाए गए हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि इसरो की करीब 120 प्रौद्योगिकियां पहले ही निजी क्षेत्र को हस्तांतरित की जा चुकी है. इसके अलावा कुलशेखरपट्टिनम (तमिलनाडु) के नए स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निजी कंपनियों के लिए खोला जा रहा है। ऐसे में कर्मचारी संगठन यह जानना चाहते हैं कि निजी भागीदारी और इसरो की अपनी तकनीकी क्षमता के बीच सरकार की स्पष्ट सीमा क्या है।

पदोन्नति पर असर की आशंका

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इसरो द्वारा प्रक्षेपण यान और उपग्रह उत्पादन से हटने की संभावना ने कर्मचारियों और उनके परिवारों में चिंता पैदा कर दी है. संगठनों का कहना है कि अगर इसरो प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के निर्माण से पूरी तरह पीछे हटता है तो इससे मौजूदा कर्मचारियों पर गंभीर असर पड़ सकता है. कर्मचारियों को दूसरे कामों में भेजे जाने, पदों की संख्या घटने या कुछ कर्मचारियों के पास पर्याप्त काम नहीं रहने की स्थिति पैदा हो सकती है. संगठनों ने आशंका जताई कि इससे तकनीकी, वैज्ञानिक, प्रशासनिक, खरीद, गुणवत्ता, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में पदोन्नति और कौशल विकास के अवसर भी कम हो सकते हैं. इसके साथ ही इसरो में भविष्य की भर्तियां घटने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रभावित होने की बात भी कही गई है।

एक्शन मोड में पीएम मोदी आज मंत्रियों की लगेगी क्लास

मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा, सोशल सेक्टर पर रहेगा खास फोकस

नई दिल्ली। सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में परफार्मेंस की समीक्षा के लिए सोमवार शाम एक अहम बैठक बुलाई गई है। इसमें खास तौर पर सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण के सेक्टर पर फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में अलग-अलग मंत्रालयों, मंत्रियों और उनके समग्र प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। समीक्षा बैठक के लिए सिर्फ उन राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के एक वर्ग को बुलाया गया है जिनका मंत्रालय सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण से संबंधित है। जिन मंत्रालयों पर कल की बैठक में फोकस रहेगा और जिनके कामकाज की समीक्षा होगी उसमें शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय आदि शामिल हैं। इसमें मंत्रियों के कामकाज का आकलन होगा। जवाबदेही पर भी चर्चा होगी. ऐसी और बैठकें भी राज्यमंत्रियों के दूसरे वर्ग के साथ आने वाले दिनों में होंगी। इन बैठकों को राज्यमंत्रियों की परफार्मेंस से भी जोड़ा जा रहा है जिसका भविष्य में होने वाली कैबिनेट फेरबदल में भी असर देखने को मिल सकता है। कैबिनेट विस्तार के समय ऐसा पहले से होता आ रहा है। कामों की हो लगातार समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में जल शक्ति मंत्रालय के दो दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा था कि सम्मेलन में दिए गए सुझावों को तय समय में लागू किया जाना चाहिए। साथ ही, इन कामों की लगातार समीक्षा भी होनी चाहिए, ताकि जरूरत के मुताबिक सुधार किया जा सके. प्रधानमंत्री ने शहरों की बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरत जैसी चुनौतियों को लेकर स्थानीय निकायों को जागरूक करने की बात कही।

सार-समाचार

महानंदा एक्सप्रेस डिरेल, कोच पटरी से उतरे

भोजपुर। बिहार के आरा में रविवार सुबह करीब 4 बजे 15483 अलीपुरद्वार जंक्शन-दिल्ली महानंदा एक्सप्रेस डिरेल हो गई। एक जनरल और एक एसी बोगी पटरी से उतर गई। घटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय-दानापुर रेलखंड पर हुई। घटना के बाद रेलवे स्टाफ और ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच हडकंप मच गया। आनन-फानन में रेलवे के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे के करीब साढ़े 3 घंटे बाद महानंदा एक्सप्रेस को रवाना किया गया। डिरेल हुई बोगियों की मरम्मत का काम जारी है। इस मामले में आरा स्टेशन के मैनेजर एनके राय को सस्पेंड कर दिया गया है। महानंदा एक्सप्रेस के डिरेल होने के कारण दिल्ली-हावड़ा रूट प्रभावित हुआ। वंदे भारत, विभूति एक्सप्रेस, गांधी धाम, कैप्टल एक्सप्रेस, इंटरसिटी, गरीब रथ, पैसेंजर, उधना एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनें लेट हैं।

बेंगलुरु में फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग

बेंगलुरु। लंदन जा रही वर्जिन अटलांटिक के विमान को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी के चलते बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ह्यआपात स्थिति में उतरना पड़ा। विमान में 270 पैसेंजर्स सवार थे। एयरपोर्ट के संचालक बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) के सूत्रों ने बताया कि विमान ने सुबह करीब 8:20 बजे हवाई अड्डे से उड़ान भरी, लेकिन उड़ान भरने के तुरंत बाद उसमें तकनीकी खराबी आ गई। इसके चलते तुमकुरु के नजदीक प्लेन ने आधे घंटे से अधिक समय तक चक्कर लगाया और फिर एहतियानत बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं।

छोटा प्लेन क्रैश होने से 2 लोगों की मौत

कैलिफोर्निया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक छोटा प्लेन क्रैश हो गया। उत्तर-पश्चिम फ्रेस्नो इलाके में ये हादसा हुआ। स्थानीय समय के अनुसार दोपहर के समय एक छोटा विमान जमीन से टकरा गया। दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। विमान ब्लाइथ एवेन्यू पर स्थित सिएरा स्काई पार्क एयरपोर्ट के पास गिरा। ये जगह शहर के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में है। अभी तक प्लेन के क्रैश होने का सही कारण पता नहीं चल पाया है। अधिकारी इसकी पूरी जांच कर रहे हैं। हादसे की खबर मिलते ही कई विभाग घटनास्थल पर पहुंचे। फ्रेस्नो पुलिस डिपार्टमेंट, फ्रेस्नो फायर डिपार्टमेंट, पीजी एंड ई, फ्रेस्नो काउंटी शेरिफ ऑफिस और नॉर्थ सेंट्रल फायर डिपार्टमेंट ने मिलकर काम शुरू किया।

ज्वालामुखी फटा, 209 उड़ानें प्रभावित

जकार्ता। इंडोनेशिया में अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में रविवार तडके विस्फोट हुआ। इससे निकली राख पश्चिमी इंडोनेशिया के कई हिस्सों में फैल गई। राख के कारण जकार्ता के सुकर्णो-हट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानें रोकनी पड़ीं। इससे कुल 209 उड़ानें प्रभावित हुईं और करीब 22,800 यात्री परेशान हुए। इनमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानें शामिल हैं। ज्वालामुखी जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच सुंडा स्ट्रेट में स्थित है। शनिवार से इसकी गतिविधियां बढ़ रही थीं। रविवार सुबह 3:53 बजे करीब 30 सेकंड तक विस्फोट हुआ। इसके बाद राख के दो बड़े गुबार बने।

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख हमारे नक्शे के मुताबिक दिखें, हमारी सीमाएं अटल, इनसे समझौता नहीं

नई दिल्ली। भारत ने दुनिया के नए नक्शे को लेकर आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख समेत भारत का पूरा इलाका भारत के आधिकारिक नक्शे के हिसाब से ही दिखना चाहिए। भारत के इलाके को गलत या भ्रामक तरीके से दिखाना हमें मंजूर नहीं है। भारत की सीमाएं अटल हैं, इससे समझौता नहीं हो सकता। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जिसमें दुनिया के नक्शे पर देशों और महाद्वीपों का आकार उनके असली क्षेत्रफल के करीब दिखाने की बात कही गई है। हालांकि, भारत ने साफ किया कि इसका मतलब किसी एक खास नक्शे को मंजूरी देना नहीं है। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुक्रवार को दुनिया के नक्शे को नए तरीके से दिखाने का प्रस्ताव पास किया।

अमेरिका में वोटर लिस्ट की राष्ट्रीय छंटनी की तैयारी, ट्रम्प प्रशासन बनाएगा डेटाबेस

10 लाख भारतवंशी वोटरों के नाम कटने का खतरा

न्यूयॉर्क। अमेरिका में आगामी मिडटर्म चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक कदम उठाया जा रहा है। ट्रम्प प्रशासन देशभर के अलग-अलग राज्यों की मतदाता सूचियों और सरकारी रिकॉर्ड का डिजिटल मिलान कर नेशनल वोटर डेटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया में जुटा है। इसके लिए करीब 125 करोड़ रुपये का फंड जारी किए जाने की जानकारी है। इस प्रक्रिया का असर अमेरिका में रहने वाले भारतवंशी मतदाताओं पर भी पड़ सकता है। अमेरिका में करीब 26 लाख भारतवंशी वोटर बताए जाते हैं। इनमें से करीब 10 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड जांच के दायरे में आने की आशंका जताई गई है। हालांकि कितने नाम वास्तव में हटेंगे, यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। अमेरिका में भारत की तरह पूरे देश की वोटर लिस्ट तैयार करने और चुनाव कराने वाली एक केंद्रीय चुनाव संस्था नहीं है। अलग-अलग राज्यों और स्थानीय प्रशासन के पास मतदाता पंजीकरण की जिम्मेदारी है। इसी वजह से राज्यों के नियम और वोटर पहचान की व्यवस्था भी अलग-अलग है। ट्रम्प प्रशासन की पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अलग-अलग राज्यों के रिकॉर्ड को सरकारी डेटाबेस से मिलाना है। वोटर की जानकारी को इमिग्रेशन रिकॉर्ड समेत दूसरे उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड से क्रॉस-चेक किया जाएगा। यानी भारत की एसआईआर जैसी प्रक्रिया में जहां फील्ड वेरिफिकेशन प्रमुख हिस्सा है, अमेरिका में इस पहल का जोर डिजिटल रिकॉर्ड मिलान और डेटाबेस तैयार करने पर है।

मंत्री सुदिव्य सोनू का हार्ट अटैक से निधन

गिरिडीह। झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर लीडर सुदिव्य कुमार सोनू का शनिवार देर रात निधन हो गया। वो गिरिडीह स्थित अपने आवास पर थे। बताया जा रहा है कि रात में सोने जाने के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। परिजनों ने उन्हें तत्काल गिरिडीह के निजी मर्सी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर शहजाद शेख ने बताया कि मंत्री सुदिव्य सोनू रात 2.15 बजे के करीब आए। उनकी छाती में दर्द हो रहा था। डॉक्टर शहजाद शेख के अनुसार, जब मंत्री अस्पताल पहुंचे थे, उस समय उन्होंने दर्द के दौरान उल्टी की, वो उनके लंग्स में चला गया था। तत्काल इलाज शुरू किया गया। सांस की नली साफ की गई। इसके बाद इसीजी निकाली गई। उसमें हार्ट अटैक के लक्षण थे। बीपी मिल नहीं रहा था।

मिस्र में ड्रग्सः टीवी एंकर सारा खलीफा सहित 12 को मौत की सजा

काहिरा। मिस्र में एक हाई-प्रोफाइल ड्रग्स मामले ने देश को स्तब्ध किया है, जहाँ चर्चित टेलीविजन प्रजेंटर सारा खलीफा को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। उनके साथ मामले में 11 अन्य आरोपियों को भी फांसी की सजा दी गई है। यह चौंकाने वाला फैसला सरकारी मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि मादक पदार्थों के निर्माण और उनकी अंतरराष्ट्रीय तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क का खुलासा है। सारा खलीफा, जिन्होंने टीवी पर अपनी पहचान बनाई थी, अब इस गंभीर आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा होने के आरोप में दोषी साबित हुई हैं। उनकी सार्वजनिक हस्ति ने इस केस को मिस्र में अभूतपूर्व चर्चा का विषय बना दिया है। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखकर कुल 12 आरोपियों को सबसे कठोर सजा सुनाई है, जो देश में ड्रग्स अपराधों के खिलाफ सख्त रुख का संकेत देता है। हालांकि, मौत की सजा के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रियाएँ भी महत्वपूर्ण होंगी, जिनसे अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।

बाढ़ ने नेपाल की अर्थव्यवस्था को डुबोया, 400 अरब का नुकसान, बिजली से पर्यटन तक संकट

1,344 शव मिले, 5 हजार लोग अब भी लापता

राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। अब तक 13,101 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका था,

काठमांडू। नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ का असर अब सिर्फ जान-माल के नुकसान तक सीमित नहीं है। शुरूआती आकलन में करीब 400 अरब नेपाली रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। अब तक 13,101 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका था, लेकिन करीब 5 हजार लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। अब तक 1344 शव मिलने की जानकारी सामने आई है। नेपाली सेना और सुरक्षा एजेंसियां प्रभावित इलाकों में तलाशी और राहत अभियान चला रही हैं। कई स्थानों पर संपर्क और आवाजाही बहाल करना भी चुनौती बना हुआ है। बाढ़ ने सडक, पुल, बिजली परियोजनाओं और खेती को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। दूसरी ओर सितंबर से नवंबर के पीक टूरिस्ट सीजन से ठीक पहले विदेशी पर्यटकों की बुकिंग कैंसिल होने लगी है। यानी नेपाल एक साथ मानवीय संकट और आर्थिक नुकसान से जूझ रहा है। बाढ़ से नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र को भी बड़ा झटका लगा है। शुरूआती आकलन के अनुसार 13 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा एक सोलर प्रोजेक्ट और दो ट्रांसमिशन लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इन सबके कारण करीब 783 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता प्रभावित होने की बात सामने आई है। नेपाल जैसे देश के लिए यह नुकसान महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी बिजली व्यवस्था में जल विद्युत की बड़ी भूमिका है। ऐसे में बाढ़ से प्रभावित परियोजनाओं की मरम्मत और उत्पादन सामान्य करने में समय लग सकता है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के शुरूआती आकलन के मुताबिक करीब 7570 घर प्रभावित हुए हैं। लगभग 55 किलोमीटर सडकें क्षतिग्रस्त हुई हैं। 37 सडक पुल और 68 झूला पुल भी टूटे या प्रभावित हुए हैं। बाढ़ ने 1806 हेक्टेयर कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचाया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय लोगों की आजीविका पर लंबे समय तक असर पड? की आशंका है।

बाढ़ की तस्वीरों से पर्यटन कारोबार को झटका

आपदा का असर अब नेपाल के पर्यटन उद्योग पर दिखाई देने लगा है। सितंबर से नवंबर तक नेपाल में पर्यटन का पीक सीजन होता है, लेकिन बाढ़ की तस्वीरों और खबरों के कारण विदेशी पर्यटक अपनी यात्राएं रद्द कर रहे हैं। काठमांडू के एक होटल में करीब 20 प्रतिशत बुकिंग कैंसिल होने की जानकारी सामने आई है। होटल कारोबारियों के अनुसार बाढ़ के बाद ऑनलाइन बुकिंग में कैंसिलेशन तेजी से बढ़ा है। सरकार को अब यह डर है कि यदि पर्यटकों के बीच यह संदेश गया कि पूरा नेपाल बाढ़ से प्रभावित है, तो इसका असर होटल, ट्रैवल एजेंसियों, गाइड, परिवहन और स्थानीय कारोबार पर भी पड़ेगा।

दैनिक प्रभात परिक्रमा

भोपाल, सोमवार 7 सितंबर 2026

संपादकीय

भ्रष्टाचार की दीमक- सरकारी दावों के बीच 70 हजार से ज्यादा शिकायतें

भ्रष्टाचार की समस्या केवल कुछ सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, निर्माण, राजस्व, खनन और व्यापार जैसे अनेक क्षेत्रों में इसके अलग-अलग रूप दिखाई देते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक और विकासशील देश के लिए भ्रष्टाचार एक गंभीर चुनौती है। जब सार्वजनिक पद और संस्थाओं का उपयोग निजी लाभ के लिए होता है, तो यह व्यवस्था को पंगु बना देता है। भ्रष्टाचार के कई रूप हैं, जिनमें घूसखोरी, धन की हेराफेरी, सरकारी कार्यों में अनियमितता, भाई-भतीजावाद और चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव भी शामिल हैं। देश ने आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन भ्रष्टाचार आज भी विकास की राह में बड़ी बाधा बना हुआ है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की वर्ष 2025 की रिपोर्ट भी इसकी तस्दीक करती है। इसके मुताबिक, पिछले साल आयोग को सरकारी संस्थाओं के खिलाफ भ्रष्टाचार की 70 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें बैंक और रेलवे से जुड़ी थीं। ये आंकड़े सरकार के उन दावों की हकीकत बयान करते हैं, जिनमें कहा जाता है कि भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर अमल किया जा रहा है। ऐसे में सवाल सिर्फ विकास के बाधित होने या सरकारी धन के दुरुपयोग का ही नहीं है, बल्कि सरकार पर जनता के भरोसे को लेकर बढ़ते संकट का भी है। भ्रष्टाचार की समस्या केवल कुछ सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, निर्माण, राजस्व, खनन और व्यापार जैसे अनेक क्षेत्रों में इसके अलग-अलग रूप दिखाई देते हैं। इस कारण आम नागरिक को कई बार अपने जरूरी कार्यों के लिए भी अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, सरकारी सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाने पर जोर दिया जा रहा है, मगर ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव आज भी साफ नजर आता है और यही भ्रष्टाचार के खात्मे में सबसे बड़ी रुकावट है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल देश के विभिन्न बैंकों में भ्रष्टाचार से जुड़ी सबसे अधिक 9,933 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 9,520 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। इसी तरह रेलवे से संबंधित 9,381 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 8,754 शिकायतों का निपटारा किया गया। तीसरे स्थान पर आवास और शहरी मामलों का विभाग है, जिसको 6,531 शिकायतें आयोग के पास दर्ज हुईं। ये तीनों सरकारी महकमे ऐसे हैं, जिनसे आम लोगों का सबसे ज्यादा सरोकार रहता है। भ्रष्टाचार की दीमक किस तरह फैल रही है, यह अब कोई छिपी बात नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पर ईमानदारी और नैतिक मूल्यों में गिरावट तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता, कमजोर निगरानी और दोषियों को समय पर सजा न मिलने से भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत की अगस्त 2026 की अमेरिका यात्रा को केवल प्रवासी भारतीयों के एक कार्यक्रम तक सीमित करके देखना उसके व्यापक अर्थ को छोटा करना होगा। न्यूयार्क में 29 अगस्त को आयोजित 'एक विश्व, एक मानवता' कार्यक्रम में उनका संबोधन ऐसे समय हुआ, जब संघ को लेकर भारत ही नहीं, विदेशों में भी अनेक धारणाएं, आरोप और पूर्वाग्रह सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे वातावरण में भागवत ने जिस प्रकार विविधता, संवाद, सेवा, सह-अस्तित्व और मानवीय एकात्मता को केंद्र में रखा, उसने संघ की विचारधारा को उसके समर्थकों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक समाज के सामने भी एक अलग दृष्टि से प्रस्तुत किया।

मोहन भागवत की अमेरिका यात्रा- भारतीय चिंतन की सार्थक प्रस्तुति

(ललित गर्ग)

मोहन भागवत ने अमेरिका में भारत की विविधता को उसकी कमजोरी नहीं, शक्ति बताया। उनके अनुसार विविधता और एकता भारत के स्वभाव में ही अंतर्निहित हैं। भारत में भाषा, जाति, पंथ, पूजा-पद्धति और परंपराओं की असंख्य धाराएं हैं, फिर भी इन्हें एक साझा सभ्यतागत चेतना जोड़ती रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत की अगस्त 2026 की अमेरिका यात्रा को केवल प्रवासी भारतीयों के एक कार्यक्रम तक सीमित करके देखना उसके व्यापक अर्थ को छोटा करना होगा। न्यूयार्क में 29 अगस्त को आयोजित 'एक विश्व, एक मानवता' कार्यक्रम में उनका संबोधन ऐसे समय हुआ, जब संघ को लेकर भारत ही नहीं, विदेशों में भी अनेक धारणाएं, आरोप और पूर्वाग्रह सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे वातावरण में भागवत ने जिस प्रकार विविधता, संवाद, सेवा, सह-अस्तित्व और मानवीय एकात्मता को केंद्र में रखा, उसने संघ की विचारधारा को उसके समर्थकों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक समाज के सामने भी एक अलग दृष्टि से प्रस्तुत किया। यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और उसके विचार अब भारत की सीमाओं से बाहर भी व्यापक चर्चा का विषय बन रहे हैं। भागवत का अमेरिका जाना वस्तुतः संघ के विचार को प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से समझाने का अवसर बना। संघ के बारे में भारत में लंबे समय से दो विपरीत धारणाएं दिखाई देती रही हैं। एक पक्ष उसे भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभावना, सेवा और सामाजिक संगठन की विराट शक्ति मानता है, जबकि दूसरा पक्ष उसके विचारों को संकीर्ण धार्मिक राजनीति से जोड़कर देखता है। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने समय-समय पर संघ और उसके विचारों पर गंभीर राजनीतिक प्रश्न उठाए हैं। अमेरिका में भी कार्यक्रम से पहले कुछ संगठनों और राजनीतिक व्यक्तियों ने भागवत की यात्रा और संघ की विचारधारा पर आपत्तियां व्यक्त कीं। ऐसे माहौल में किसी संस्था की वास्तविक छवि केवल आरोप-प्रत्यारोप से नहीं बनती, वह संवाद से बनती है। यही इस यात्रा का सबसे बड़ा महत्व है। भागवत ने अपने विचार विरोधियों पर आक्रमण करके नहीं, बल्कि भारतीय चिंतन की व्याख्या करके सामने रखे। इससे संघ को लेकर बनी धारणाओं पर सहज रूप से नया आधार तैयार हुआ।

न्यूयार्क में भागवत के वक्तव्य का सबसे अधिक चर्चित पक्ष उनका हिंदू-मुस्लिम संबंधों पर स्पष्ट कथन रहा। उन्होंने कहा कि यदि कोई हिंदू यह मानता है कि भारत में मुसलमानों के लिए स्थान नहीं होना चाहिए, तो वह हिंदू नहीं रह सकता। यह कथन राजनीतिक नारे से अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें हिंदुत्व की उनकी व्याख्या को सामाजिक समावेश के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने यह रेखांकित किया कि सत्य एक है और उसे समझने तथा व्यक्त करने के मार्ग अलग-अलग हो सकते हैं। भारतीय परंपरा की यही विशेषता है कि वह सह-अस्तित्व को केवल सहनशीलता के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की विविध अभिव्यक्ति के रूप में देखने की क्षमता रखती है। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है-यदि हिंदुत्व का अर्थ भारत की सांस्कृतिक चेतना है, तो क्या वह किसी समुदाय को भारत से बाहर कर सकता है? भागवत का उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक दिखाई देता है। उनका कथन हिंदुत्व को उस

व्याख्या की सामने रखता है, जिसमें भारतीयता किसी एक पूजा-पद्धति की कसौटी नहीं, बल्कि साझा सांस्कृतिक विरासत है।

भागवत ने अमेरिका में भारत की विविधता को उसकी कमजोरी नहीं, शक्ति बताया। उनके अनुसार विविधता और एकता भारत के स्वभाव में ही अंतर्निहित हैं। भारत में भाषा, जाति, पंथ, पूजा-पद्धति और परंपराओं की असंख्य धाराएं हैं, फिर भी इन्हें एक साझा सभ्यतागत चेतना जोड़ती रही है। यह संदेश आज के विश्व के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। अनेक देशों में धार्मिक पहचान, नस्लीय भेद, सांस्कृतिक असहमति और राजनीतिक ध्रुवीकरण सामाजिक तनाव बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय भारत का अनुभव यह बताता है कि भिन्नताओं को मिटाना आवश्यक नहीं, उन्हें सम्मान देकर भी एकता स्थापित की जा सकती है। यही विचार भागवत के संबोधन को सामान्य राजनीतिक भाषण से ऊपर उठाता है। उनका आग्रह था कि विविधता को स्वीकार ही नहीं, सम्मान और संवाद भी मिलना चाहिए। संघ की सार्वजनिक छवि का बड़ा हिस्सा राजनीतिक विमर्श से निर्मित हुआ है, जबकि संघ अपने को सामाजिक संगठन और सेवा-आधारित सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। भागवत ने अमेरिका में भी सेवा, सामाजिक समरसता और संवाद को परिवर्तन का आधार बताया। यहीं से यह प्रश्न उठता है कि संघ की छवि को केवल चुनावी राजनीति के चश्मे से देखने की सीमा सामने आती है। किसी संगठन को समझने के लिए, उसके राजनीतिक प्रभाव के साथ उसकी सामाजिक गतिविधियों, सेवा-कार्य, संगठनात्मक संस्कृति और वैचारिक आधार को भी देखना आवश्यक है। भागवत की यात्रा ने कम से कम इतना अवसर अवश्य दिया कि संघ को उसके आलोचकों के शब्दों और उसके समर्थकों की प्रशंसा से अलग, उसकी अपनी व्याख्या के आधार पर सुना जाए।

अमेरिका में बसे भारतीयों से भागवत ने एक संतुलित संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिस देश में वे रह रहे हैं, वह उनकी कर्मभूमि है और वहां के प्रति उनकी निष्ठा तथा दायित्व स्वीकार्य हैं। साथ ही भारत उनकी जन्मभूमि है, जिससे उन्हें मानवीय मूल्यों और सांस्कृतिक संस्कारों की विरासत मिली है। यह दृष्टि प्रवासी भारतीयों के सामने पहचान के संघर्ष के बजाय पहचान के समन्वय का मार्ग रखती है। अपनी जड़ों से जुड़े रहना और जिस समाज में रह रहे हैं उसके प्रति पूर्ण निष्ठा रखना-दोनों एक साथ संभव हैं। यही भारतीय संस्कृति की उदारता है। यह भी तथ्य है कि भागवत के कार्यक्रम का अमेरिका में विरोध हुआ और संघ की विचारधारा को लेकर तीखी आलोचनाएं सामने आईं। लेकिन लोकतांत्रिक समाज में किसी विचार का उत्तर उसे रोककर नहीं, उसके साथ संवाद करके दिया जाता है। इस दृष्टि से यह यात्रा संघ के लिए भी एक परीक्षा थी। भागवत ने विरोध का उत्तर आक्रामक भाषा में देने के बजाय एकात्मता, मानवता और सह-अस्तित्व की बात की। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। आलोचक उनके शब्दों और संघ के व्यवहार के बीच अंतर का प्रश्न उठा रहे हैं, समर्थक इसे संघ के मूल विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति मान रहे हैं। इस बहस का अंतिम निर्णय समय और व्यवहार करेगा, लेकिन इतना निश्चित है कि बहस अब अधिक प्रत्यक्ष और वैश्विक हो गई है। मोहन भागवत की अमेरिका यात्रा को संघ की छवि पर वर्षों से चले आ रहे विवाद का अंतिम उत्तर मानना अतिशयोक्ति होगी। किंतु इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ अवश्य कहा जा सकता है। जिन लोगों ने संघ को केवल राजनीतिक आरोपों और विरोधी व्याख्याओं के माध्यम से जाना है, उन्हें पहली बार इतने बड़े वैश्विक मंच पर उसके शीर्ष नेतृत्व की विचार-दृष्टि को सीधे सुनने का अवसर मिला। यह यात्रा संघ के लिए एक उजाला इसलिए बनी है कि इसमें प्रतिरोध की भाषा कम और आत्मविश्वास की भाषा अधिक दिखाई दी। इसमें यह कहने का प्रयास था कि भारतीयता किसी के निषेध से नहीं, सबके सम्मान से मजबूत होती है, हिंदुत्व किसी समुदाय के बहिष्कार से नहीं, मानवता की एकात्म दृष्टि से सार्थक होता है और भारत की शक्ति उसकी समानता में नहीं, उसकी विविधताओं के बीच बनी रहने वाली सांस्कृतिक एकता में है। आज विश्व को केवल आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति और तकनीकी प्रगति की आवश्यकता नहीं है। उसे ऐसा जीवन-दर्शन भी चाहिए जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ सके। भागवत के अमेरिकी संबोधन में भारत की इसी भूमिका की कल्पना दिखाई दी-एक ऐसा भारत जो अपनी परंपरा के बल पर विश्व को सह-अस्तित्व, संवाद और एकात्मता का रास्ता दिखा सके। मोहन भागवत की यह यात्रा इसलिए स्मरणीय रहेगी कि उसने संघ के बारे में चल रही बहस को भारत की सीमाओं से निकालकर विश्व के सार्वजनिक विमर्श में पहुंचा दिया। अब संघ की पहचान केवल उसके विरोधियों के आरोपों या समर्थकों के दावों से नहीं, बल्कि उसके विचार, उसके व्यवहार और समाज के साथ उसके संवाद से तय होगी। अंततः किसी विचारधारा की सबसे बड़ी शक्ति उसका प्रचार नहीं, उसका आचरण होता है। अमेरिका की धरती से भागवत ने जो संदेश दिया है, उसकी वास्तविक कसौटी भारत की धरती पर सामाजिक समरसता, सेवा, संवाद और सह-अस्तित्व के रूप में दिखाई देगी। यदि यह संदेश व्यवहार में उतरता है, तो यह केवल संघ की छवि को नहीं, भारत की वैश्विक सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को भी नई ऊंचाई दे सकता है। लेखक, पत्रकार, स्तंभकार है। (इस लेख में लेखक के अपने विचार है।)

संघ प्रमुख ने अपने विदेश प्रवास में दिया मानवता का संदेश

विगत दिनों अमेरिकन हिंदूज फार एंगेजमेंट एंड डायलॉग संस्था द्वारा न्यूयॉर्क स्थित मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में आयोजित यूनिवर्सल ब्रदरहुड सेलिब्रेशन (वन वर्ल्ड वन ह्यूमैनिटी) कार्यक्रम में व्याख्यान देने हेतु संघ प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका पहुंचने के पूर्व ही वहां संघ के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त जो सुनियोजित अभियान छेड़ा गया वह मोहन भागवत के इस बहुप्रतीक्षित अमेरिका प्रवास को आशातीत सफलता प्रदान करने में बहुत मददगार साबित हुआ। मोहन भागवत का पुरजोर विरोध करने वालों में सबसे प्रमुख नाम न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का था जिन्हें यह पता भी नहीं मालूम था कि संघ प्रमुख के प्रस्तावित कार्यक्रम को अनुमति न देने का अधिकार न्यूयॉर्क के मेयर के पास नहीं है। अमेरिका में संघ प्रमुख के कार्यक्रम को विफल बनाने के लिए की गई उनकी अनावश्यक बयानबाजी को न्यूयॉर्क में न केवल बड़े पैमाने पर नापसंद किया गया बल्कि उस बयानबाजी ने दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के विचार जानने के लिए उत्सुक न्यूयॉर्क शहर के लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। परिणाम यह हुआ कि संघ प्रमुख के द्वारा इस कार्यक्रम में व्यक्त किए गए विचारों ने न्यूयॉर्क के बड़बोले मेयर की बोलती ही बंद कर दी और अब उन विचारों की गूंज आज सारी दुनिया में सुनाई दे रही है। अब शायद न्यूयॉर्क के जोहरान ममदानी को भी यह आभास हो गया होगा कि संघ प्रमुख का यह बहुप्रतीक्षित अमेरिका-प्रवास न्यूयॉर्क से अखिल विश्व को मानवता का संदेश देने के लिए हुआ था। बेहतर होता कि जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर में संघ प्रमुख के इस सफल कार्यक्रम के पश्चात, रस्म अदायगी के लिए ही सही, अमेरिकन हिन्दूज फार एंगेजमेंट एंड डायलॉग संस्था के प्रति आभार व्यक्त करते। आखिरकार, यह एक ऐसा आयोजन था जिस पर सारी दुनिया की नजरें टिकी हुई थीं। जोहरान ममदानी सहित जो मुट्ठी भर संगठन इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे उनसे अब यह सवाल तो पूछा ही जा सकता है कि संघ प्रमुख ने कार्यक्रम के मंच से अपने संबोधन में सारी दुनिया को मानवता का जो संदेश दिया क्या वह आज की उथल पुथल भरी दुनिया में पूरी तरह प्रासंगिक नहीं है। जोहरान ममदानी सहित कुछ मुट्ठी भर संगठनों के अनपेक्षित विरोध के बावजूद मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में 39 राज्यों के 853 शहरों के लगभग 6000 हजार से अधिक प्रबुद्ध जन संघ प्रमुख के विचारों को सुनने के लिए पहुंचे और कार्यक्रम की शानदार सफलता सुनिश्चित करने में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। गौरतलब है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत 2018 में भी वर्ल्ड हिन्दू कांग्रेस को संबोधित करने के लिए अमेरिका प्रवास पर गए थे जहां उन्होंने विश्व के 60 देशों से आए 2500 प्रतिनिधियों के समक्ष अपना सारगर्भित व्याख्यान दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने पहले कार्य काल में जब अमेरिका प्रवास पर आए थे तब उन्होंने भी मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में अपना पहला व्याख्यान दिया था।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर देश विदेश में किए जा रहे आयोजनों की श्रृंखला के अन्तर्गत ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम के तहत न्यूयॉर्क में आयोजित कार्यक्रम के मंच से संघ प्रमुख ने एक ओर जहां सारी दुनिया को मानवता का संदेश दिया वहीं दो टूक लहजे में यह भी कहा कि अगर कोई हिन्दू यह सोचता है कि देश में मुसलमान नहीं होने चाहिए तो वह हिन्दू नहीं रह सकता। हिन्दू होने का मतलब यह मानना है कि सभी रास्ते एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं और हर इंसान को गरिमापूर्ण समान है। संघ प्रमुख ने अपनी इस बात पर विशेष जोर दिया कि विविधता में एकता भारत के डीएनए में है। लोगों के नाम, शरीर, पूजा पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं परंतु हम सबको जोड़ने वाला स्वरूप एक ही है। सबके अंदर आत्मा है मौजूद है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। भागवत ने कहा कि ब्रह्माण्ड और जीवन को संभालने वाली व्यवस्था धर्म है। यही व्यवस्था जीवन को अलग अलग स्थितियों में संतुलन बनाती है।

संघ प्रमुख ने कहा कि मनुष्य के पास जो सोचने की क्षमता है वह एक वरदान है परंतु असली महत्व इस बात का है कि हम किस तरह सोचते हैं। सही सोच हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। संघ प्रमुख ने कहा कि प्रवासी भारतीयों की पहली जिम्मेदारी अपनी कर्म भूमि के प्रति है। उन्हें अपनी कर्म भूमि के प्रति वफादार रहते हुए भारत के मूल्यों को अपनाकर उसके अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। इसी क्रम में संघ प्रमुख ने आगे कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना कमाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कितना बांटते हैं। भागवत ने कहा कि कमाई के साथ सेवा और आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। भौतिक सुविधाएं स्थायी सुख और संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकतीं। संघ प्रमुख ने व्यक्ति, समाज और पर्यावरण के समान रूप से विकास पर जोर देते हुए कहा कि इसी तरह मनुष्य के शरीर, मन और बुद्धि का विकास भी आवश्यक है। संघ प्रमुख ने स्वामी विवेकानंद का उल्लेख करते हुए कहा कि हर देश का एक मकसद और एक नियति होती है। भारत की नियति दुनिया को यह एहसास कराना है कि हम एक हैं। 9 कृष्णमोहन झा/

(लेखक राजनैतिक विश्लेषक हैं)

बाघ बचेंगे तो जंगल बचेंगे- संरक्षण के बावजूद क्यों बढ़ रही है उनके सामने चुनौती

दरअसल, मानव समाज के मन-मस्तिष्क में बाघों के प्रति उस प्रेम और संवेदना का सदा से अभाव रहा है, जिसके वे अधिकारी हैं। यही कारण है कि जो बाघ कभी बहुतायत में पाए जाते थे, आज वे दुनिया भर में कम होते जा रहे हैं। पिछली एक सदी में दुनिया भर से लाखों की संख्या में बाघ या तो शिकारियों द्वारा मारे जा चुके हैं या आपसी संघर्ष, बीमारी या किसी अन्य कारण से उनकी मौत हो गई। भारत समेत विभिन्न देशों की सरकारों, एजेंसियों और संगठनों की तमाम घोषणाओं, दावों और वादों के बावजूद दुनिया भर में बाघों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। बाघों की इस दुर्दशा के कारण ही अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इन्हें विलुप्ति की कगार पर खड़े जीवों की श्रेणी में डाल रखा है।

(चेतनादित्य आलोक)

मानव समाज के मन-मस्तिष्क में बाघों के प्रति उस प्रेम और संवेदना का सदा से अभाव रहा है, जिसके वे अधिकारी हैं। देश में बाघों के संरक्षण को लेकर सरकार की ओर से कई कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन धरातल पर इनका असर अपेक्षा के अनुरूप देखने को नहीं मिल रहा है। इसका एक कारण इस वन्य प्राणी को लेकर मानव समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव है। जबकि सच तो यह है कि बाघ हमारे पर्यावरण और प्रकृति के लिए ही नहीं, बल्कि मानव जीवन के अस्तित्व के लिए भी उपयोगी है। ये जीव पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, क्योंकि आहार जगत में इन्हें शिकारी के रूप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है।

जंगल में इनका भोजन भंडार सबसे बड़ा होता है। इसलिए स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में इनकी अहम भूमिका होती है। ऐसे में यदि कभी इस पृथ्वी से बाघ समाप्त हो जाएं, तो इससे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में पड़ जाएगा। बाघों की अनुपस्थिति में शाकाहारी प्राणियों की आबादी बढ़ जाएगी और आहार चक्र में असंतुलन पैदा होगा। जाहिर है, शाकाहारियों की अधिकता से वनस्पति का नुकसान होगा, जिससे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।

वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक, एक हिरण को सर्दियों के मौसम में भोजन के लिए औसतन प्रतिदिन 2.3 किलोग्राम वनस्पति की आवश्यकता होती है। वहीं, गर्मियों में इसकी मात्रा दोगुनी हो जाती है। कुल मिलाकर एक हिरण को एक वर्ष में वनस्पतियों से कुछ एक हजार किलोग्राम से अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। वहीं, एक बाघ को अपना पेट भरने के लिए प्रति वर्ष औसतन पचास हिरण के आकार के जानवर या लगभग तीन हजार किलोग्राम जीवित शिकार की जरूरत होती है। यानी एक बाघ प्रति वर्ष पचास हिरणों को खाकर पृथ्वी पर लगभग पचास हजार किलोग्राम वास्तविक भोजन बचाता है, जो जंगल में शेष हिरणों अथवा अन्य शाकाहारी प्राणियों के जीवन यापन के लिए तथा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। इस दृष्टि से जैव विविधता के संरक्षण एवं जंगलों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने वाली प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में भी बाघों का विशेष योगदान है।

दरअसल, मानव समाज के मन-मस्तिष्क में बाघों के प्रति उस प्रेम और संवेदना का सदा से अभाव रहा है, जिसके वे अधिकारी हैं। यही कारण है कि जो बाघ कभी बहुतायत में पाए जाते थे, आज वे दुनिया भर में कम होते जा रहे हैं। पिछली एक सदी में दुनिया भर से लाखों की संख्या में बाघ या तो शिकारियों द्वारा मारे जा चुके हैं या आपसी संघर्ष, बीमारी या किसी अन्य कारण से उनकी मौत हो गई। भारत समेत विभिन्न देशों की सरकारों, एजेंसियों और संगठनों की तमाम घोषणाओं, दावों और वादों के बावजूद दुनिया भर में बाघों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। बाघों की इस दुर्दशा के कारण ही अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इन्हें विलुप्ति की कगार पर खड़े जीवों की श्रेणी में डाल रखा है।

भारत की बात करें, तो इस वर्ष जनवरी से मार्च के बीच 42 बाघों की मौत हुई। यह आंकड़ा वन्यजीव, विशेष रूप से बाघ संरक्षण को लेकर देश के संवेदनशील नागरिकों एवं पशु प्रेमियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें, तो वर्ष 1900 में देश में बाघों की संख्या 40 हजार से भी ज्यादा थी, जबकि आज इनकी संख्या घट रही है। भारत में बाघों की इस दुर्दशा के लिए विशेष रूप से ब्रिटिश सरकार की वन्यजीव विरोधी नीतियां जिम्मेदार रही हैं। वर्ष 1906 में प्रकाशित सोडब्लू मरफी की पुस्तक 'अ गाइड टू नैनीताल एंड कुमाऊं' में कुछ सूचियां और सरकारी नियमावलियां दी गई हैं, जो वन्यजीवों के प्रति ब्रिटिश हुकूमत के क्रूर व्यवहार को दर्शाती हैं।

ब्रिटिश राज में वन्यजीवों की हत्या करने पर सरकार की ओर से इनाम दिए जाते थे, जिनमें आठ आने से लेकर दस रुपए तक के इनाम निर्धारित थे। इनमें सर्वाधिक दस रुपए के इनाम भेड़ियों और बाघों को मारने पर दिए जाने का प्रावधान था। भारत में बाघों के संरक्षण एवं निगरानी का कार्य राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को सौंपा गया है। यह केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन देश में बाघों के संरक्षण एवं निगरानी को पेशेवर रूप देने के उद्देश्य से दिसंबर, 2005 में गठित प्रमुख वैधानिक संस्था है। बाघों के संरक्षण एवं निगरानी के कार्य में लगातार सुधार करते हुए इसे और अधिक बेहतर बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाना इस प्राधिकरण के लक्ष्यों में शामिल है।

जाहिर है, अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न राज्यों में 'प्रोजेक्ट टाइगर' का संचालन एवं संरक्षण योजनाओं को मंजूरी देने के अतिरिक्त बाघों के आवासों की निगरानी तथा मानव एवं वन्यजीवों के बीच होने वाले संघर्षों के समाधान ढूंढने में भी यह प्राधिकरण महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में बाघों की संख्या में हुई उत्साहजनक वृद्धि केवल प्राधिकरण तथा अन्य वन्यजीव संरक्षण एजेंसियों की संरक्षण नीतियों और योजनाओं का ही परिणाम नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक से युक्त बाघ संरक्षण प्रणाली और जनभागीदारी के सफल प्रयोग का भी नतीजा है। पिछले एक दशक में विज्ञान और तकनीक ने देश में बाघ संरक्षण की तस्वीर बदल दी है। इससे पहले वन कर्मियों को कई दिनों तक जंगलों में पैदल घूमकर वन्यजीवों के पदचिह्नों के आधार पर अनुमान लगाना पड़ता था, जबकि आज आधुनिक तकनीकों ने बाघ संरक्षण को अधिक सटीक, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने का कार्य किया है।

इन सभी तकनीकों में कैमरा ट्रैप बाघ संरक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाली सबसे विश्वसनीय प्रणाली मानी जा रही है। वन्यजीव संरक्षण एजेंसियों की नीतियों, योजनाओं एवं आधुनिक तकनीकों के उपयोग सहित सरकार के अधीन बाघ संरक्षण के लिए किए जाने वाले समेकित प्रयासों से देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसने आज वैश्विक मंच पर भारत को एक सकारात्मक पहचान दिलाने का कार्य किया है। आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2006 में जहां देश में केवल 1,411 बाघ थे, वहीं 2022 तक यह संख्या बढ़कर 3,682 हो गई। वैसे 2025 में देश में कुल 167 बाघों की मौतें भी दर्ज की गईं, जिनमें 31 शावक शामिल थे। पिछले चार वर्षों में बाघों की कुल संख्या के अनुपात में मृत्यु दर पांच फीसद से नीचे है, जिसे संरक्षण की दृष्टि से सकारात्मक माना जा रहा है।

आज दुनिया भर के जंगलों में लगभग 5,574 बाघ ही बचे हुए हैं, इनमें लगभग तीन-चौथाई बाघ भारत में हैं। 'साइंस' पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, वर्ष 2010 से 2022 तक भारत में बाघों की अनुमानित संख्या 1,706 के मुकाबले 2025 में दोगुनी से भी अधिक 3,700 के लगभग पहुंच गई। हालांकि, यह आंकड़ा अभी संतोषजनक स्थिति से बहुत कम है। बाघ संरक्षण के कार्य में चुनौतियां आज भी कायम हैं। सबसे जरूरी है बाघों के प्राकृतिक आवास को बचाना। विकास के नाम पर वनों की अंधाधुंध कटाई से वन्यजीवों का आवास नष्ट हो रहा है और वे भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे मानव के साथ उनका संघर्ष भी बढ़ रहा है।

फटाफट खबरें

11 साल में 13वीं बार मेट्रो में सफर पर निकले पीएम मोदी, छात्रों और यात्रियों से की बातचीत

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली मेट्रो से पहुंचे। मेट्रो में उनके हाथ में कार्ड था। सफर के दौरान उन्होंने छात्रों और अन्य यात्रियों से बातचीत की। वर्ष 2023 के बाद यह प्रधानमंत्री की दिल्ली मेट्रो में पहली यात्रा है।सितंबर 2023 में यशोभूमि के उद्घाटन के दौरान उनकी मेट्रो यात्रा को 12वीं यात्रा बताया गया था। शनिवार की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री अब तक 13 बार दिल्ली मेट्रो में सफर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने करीब 11 साल पहले दिल्ली मेट्रो से सफर की शुरूआत की थी। अप्रैल 2015 में उन्होंने पहली बार धौला कुआं से द्वारका तक मेट्रो की सवारी की थी। उन्हें राष्ट्रीय खुफिया अकादमी के एक कार्यक्रम में शामिल होना था। वीवीआईपी आवाजाही से सड़क पर आम लोगों को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए उन्होंने मेट्रो से जाने का फैसला किया था। पहली यात्रा के बाद उन्होंने मेट्रो के सफर को सुखद अनुभव बताया था। इसके बाद अलग-अलग मौकों पर प्रधानमंत्री ने मेट्रो का इस्तेमाल किया। 30 जून 2023 को प्रधानमंत्री ने लोक कल्याण मार्ग से विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन तक यात्रा की थी। उनके साथ करीब 30 छात्र भी सफर कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने छात्रों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, डिजिटल अर्थव्यवस्था, तनाव से निपटने और पर्यावरण समेत कई विषयों पर बातचीत की थी। उस यात्रा को उनकी 11वीं दिल्ली मेट्रो यात्रा बताया गया था। इसके करीब ढाई महीने बाद 17 सितंबर 2023 को अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री फिर मेट्रो में सवार हुए। उन्होंने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर द्वारका सेक्टर-21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर-25 तक यात्रा की। यशोभूमि के उद्घाटन से जुड़ी इस यात्रा को उनकी 12वीं मेट्रो यात्रा बताया गया था। वापसी में भी उन्होंने मेट्रो से सफर किया और यात्रियों से बातचीत की थी।

दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव, सीएम रेखा का औचक निरीक्षण

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को लगातार हो रही बारिश के दौरान सद्भावना पार्क एवं आसपास की सड़कों का औचक निरीक्षण कर जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद कर्मचारियों से जलनिकासी की व्यवस्था और बारिश के दौरान सामने आ रही चुनौतियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलभराव वाले क्षेत्रों में तत्काल पंप एवं अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कर पानी की निकासी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बारिश के कारण दिल्लीवासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए संबंधित विभाग पूरी तत्परता और समन्वय के साथ कार्य करें।

दक्षिण दिल्ली में 28 वर्षीय माली मृत मिला

दिल्ली: दिल्ली उन्होंने बताया कि 2 सितंबर को साउथ दिल्ली के एक फार्महाउस के कमरे में इश्तियाक अली का शव औंधे मुंह पड़ा मिला। अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद से अली के साथ रहने वाला एक व्यक्ति लापता है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार, 2 सितंबर को शाम करीब 4:12 बजे घटना के बारे में ढउफ कॉल मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और अली को मृत पाया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित की गर्दन पर गंभीर चोटें थीं और उसके शरीर पर चोट के अन्य निशान भी देखे गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फोरेंसिक व क्राइम टीम ने घटनास्थल की जांच कर सबूत इकट्ठा किए। अधिकारियों ने मौके से शराब की कई बोतलें और अन्य सामान बरामद किया, जिन्हें जांच में शामिल किया गया है। पुलिस ने बताया कि शुरूआती जांच से पता चला है कि अली की आसपास काम करने वाले एक अन्य माली के साथ बहस हुई थी। उन्होंने बताया कि संदिग्ध ने कथित तौर पर झगड़े के दौरान अली पर हमला किया और घटना के बाद मौके से फरार हो गया।

सेफ सिटी प्रोजेक्ट: दिल्ली में एआई निगरानी तंत्र कैमरों से पहचानेगा पांच करोड़ चेहरे

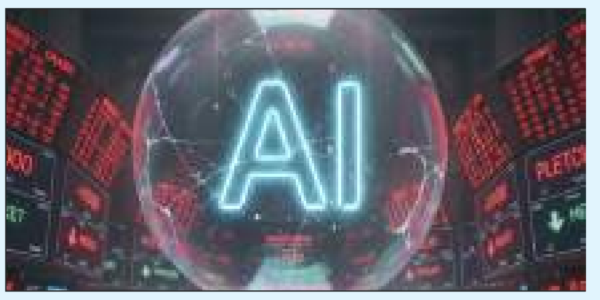

दिल्ली: दिल्ली में चप्पे-चप्पे पर लगे कैमरे न सिर्फ चेहरों की पहचान करेंगे बल्कि एआई आधारित निगरानी तंत्र से 5 करोड़ लोगों की पूरी कुंडली भी बता देंगे। राजधानी में तेजी से बढ़ रहे कैमरों का नेटवर्क कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी तंत्र से जुड़ रहा है। इससे यह फायदा होगा कि पुलिस चेहरे और वाहन की नंबर प्लेट की पहचान कर बहुत कम समय में संदिग्ध व्यक्ति तक पहुंच बना सकती है।

व्यावसायिक समाचार मंच द केन की एक महीने लंबी जांच रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस करीब 857 करोड़ रुपये के 'सेफ सिटी प्रोजेक्ट' विकसित कर रही है। रिपोर्ट के लिए कम से कम 20 पुलिस अधिकारियों, तकनीकी सेवा प्रदाताओं और सलाहकारों से बातचीत तथा परियोजना से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज की समीक्षा की गई।

रिपोर्ट के अनुसार, इस निगरानी व्यवस्था की खासियत केवल कैमरों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि अलग-अलग सरकारी रिकॉर्ड को आपस में जोड़कर किसी व्यक्ति की पहचान और पृष्ठभूमि तलाशने की क्षमता बढ़ानी है। पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र, आपराधिक न्याय व्यवस्था, मतदाता पहचान पत्र, वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े डाटाबेस इस तंत्र से जोड़े गए हैं।

इस तकनीक की उपयोगिता का एक उदाहरण अप्रैल में दिल्ली विधानसभा के बाहर सामने आया। द केन के अनुसार 37 वर्षीय एक व्यक्ति सफेद टाटा सिएरा लेकर विधानसभा के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बैरिकेड से टकराकर अंदर पहुंच गया। वह वाहन से उतरा और विधानसभा अध्यक्ष की खड़ी कार में गुलदस्ता रखने जैसी हरकत करने के बाद वहां से भाग गया। पुलिस ने उसे दो घंटे से भी कम समय में पकड़ लिया। विधानसभा से करीब चार किमी दूर पुलिस पिकेट पर सिएरा को रोका गया और चालक को हिरासत में ले लिया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्रवाई में सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मिली तकनीकी मदद महत्वपूर्ण रही। द केन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे तंत्र में तस्वीरों, वीडियो और व्यक्तिगत तथा बायोमेट्रिक जानकारी का बड़ा संग्रह तैयार हो रहा है। करीब 40 लाख व्यक्तियों से संबंधित ऐसा डेटा उपलब्ध बताया गया है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका दायरा केवल अपराधियों तक सीमित नहीं है। मतदाता पहचान पत्र रखने वाले, ड्राइविंग लाइसेंसधारी या वाहन पंजीकृत कराने वाले लोग भी संबंधित सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद हैं।

इसी तरह किरायेदारों और घरेलू कामगारों के पुलिस सत्यापन से जुड़ी जानकारी भी इस व्यापक डाटा ढांचे का हिस्सा बन सकती है।

पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र या चरित्र प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वालों का रिकॉर्ड भी पहचान संबंधी सूचनाओं को जोड़ने में इस्तेमाल किया जा सकता है।

दिल्ली ऑफिस गोलीकांड की साजिश में एक गिरफ्तार

दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में मुख्य साज़िशकर्ता माने जा रहे भूपेंद्र (उर्फ.गुड़िया उर्फ.ढोलवाला) को गिरफ़्तार किया है। तीन अन्य संदिग्धों – मोनू, दीपक भगत और रवि (उर्फ.बाबा) – की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस के मुताबिक, 3 सितंबर को जेजे कॉलोनी में ढोलवाला के ऑफि स के अंदर गोलीबारी की सूचना देने वाली एक PCR कॉल मिली थी। कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुँची और वहाँ तरुण (उर्फ. रंजन, 25 साल) और रोहित (23 साल) मिले। शुरूआती जाँच में पुलिस को पता चला कि ऑफि स के अंदर दो राउंड गोली चलाई गई थी। एक गोली रोहित की उंगली में लगी, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज की जाँच की और स्थानीय निवासियों व दुकानदारों से पूछताछ की।

शिक्षक महाकुंभ में 118 शिक्षकों का किया गया सम्मान

मुख्यमंत्री बोलीं- शिक्षक समाज के निर्माण की मजबूत नींव

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को शिक्षा दिवस पर 'शिक्षक महाकुंभ-स्टेट टीचर्स अवॉर्ड 2026' में 118 शिक्षकों को सम्मानित किया। इनमें 20 हेड ऑफ स्कूल (एचओएस), डीओई एवं एमसीडी विद्यालयों के 69 शिक्षक तथा 3 सीएम श्री स्कूलों के शिक्षक शामिल है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालयाध्यक्ष, स्पेशल एजुकेटर, खेल शिक्षकों सहित शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया।

महान शिक्षाविद् व भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के उपलक्ष्य में त्यागराज स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षकों के समर्पण, नवाचार और विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान दिया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक अभय वर्मा, नीरज बसोया, चंदन कुमार चौधरी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग की निदेशक अंकिता आनंद, कई वरिष्ठ अधिकारी सहित विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक, प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह सम्मान केवल शिक्षकों की उपलब्धियों का सम्मान नहीं, बल्कि उस समर्पण, धैर्य और विश्वास का सम्मान है, जिसके माध्यम से शिक्षक हर दिन हमारे बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के निर्माण की मजबूत नींव हैं। वे विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि उनमें संस्कार, कौशल, आत्मविश्वास, कर्तव्यबोध और जीवन की सही दिशा का भी संचार करते हैं। शिक्षक का प्रभाव केवल एक विद्यार्थी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह पूरी पीढ़ी के निर्माण में योगदान देता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि दिल्ली के हर बच्चे को ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जो उसे ज्ञान के साथ कौशल, संस्कार और आत्मविश्वास भी प्रदान करे। इसी प्रतिबद्धता के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 में शिक्षा के लिए 19,148 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। साथ ही तकनीक, स्मार्ट शिक्षण संसाधनों के माध्यम से दिल्ली के विद्यालयों को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के विद्यालयों में विद्यार्थियों की भाषा व संवाद क्षमता को मजबूत करने के लिए 170 आधुनिक लैंग्वेज लैब स्थापित की जा रही हैं, जिनमें 70 सीएम श्री स्कूल और 100 अन्य सरकारी विद्यालय शामिल हैं। इसके साथ ही नींव, राष्ट्रनीति और निपुण संकल्प जैसी पहलों के माध्यम से विद्यार्थियों में उद्यमिता, नवाचार, समस्या समाधान, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक दक्षता को मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली सरकार का संकल्प है कि अपने कार्यकाल में विद्यार्थियों और शिक्षकों से जुड़ी किसी भी समस्या को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा।दिल्ली की विभिन्न लंबित समस्याओं और पुरानी व्यवस्थागत कमियों का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की समस्याओं का स्थायी समाधान केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए नागरिकों की सोच और व्यवहार में भी बदलाव आवश्यक है। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे विद्यार्थियों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, नियमों के पालन, अनुशासन, संवेदनशीलता और जरूरतमंदों की सहायता जैसे संस्कार विकसित करें, ताकि बचपन से ही जिम्मेदार नागरिकता की नींव मजबूत हो। उन्होंने कहा कि 'गुड टच और बैड टच' जैसी आवश्यक जानकारियों के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित बनाना भी शिक्षकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

दिल्ली में नहीं रुक रहा मर्डर का सिलसिला: लाठी-डंडे से पीट-पीटकर युवक की हत्या, सीसीटीवी में कैद खौफनाक वारदात

नई दिल्ली: दिल्ली के मयूर विहार फेज-3 में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन इलाके के मयूर विहार फेज-3 में एक व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और जांच कर रही है।

सुबह के वक्त पीट-पीटकर की हत्या

मिली जानकारी के मुताबिक, ये हत्याकांड सुबह 5 बजे के करीब हुआ। युवक को लाठी और डंडे से पीट-पीटकर मारा गया है। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है और जांच कर रही है। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है।

घटना के चश्मदीद गवाह का बयान सामने आया

इस घटना में एक चश्मदीद गवाह (सिक्योरिटी गार्ड नंदलाल यादव) का कहना है, 'मैंने सुबह 4 बजे कुछ लोगों को देखा था। वे लोग मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। वे दो लोग थे।'

हाल ही में नागलोई में एक छात्र की हुई थी हत्या

दिल्ली में आए दिन हत्याओं की खबर सामने आती रहती है। हाल ही में दिल्ली के नागलोई में स्कूल जा रहे 15 साल के छात्र पर चाकू से हमला किया गया था। इस घटना में छात्र की मौत हो गई थी। छात्र पर हमले की वजह भी सामने आई थी। दरअसल छात्र ने कुछ लड़कों को एक लड़की से छेड़छाड़ करने से रोकने की कोशिश की थी, उसके बाद छात्र पर ये हमला हुआ और उसकी जान चली गई।

नरेला में प्रॉपर्टी डीलर की हुई थी हत्या

इससे पहले दिल्ली के नरेला में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई थी। नरेला में प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी गई थी। हमलावरों ने जिम के बाहर प्रॉपर्टी डीलर पर हमला किया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद की हत्या की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुर ने ली है।

दिल्ली के धुबी घाट में भी हुई थी हत्या

इसके अलावा दिल्ली के धुबी घाट में भी एक दोस्त ने चाकू से गोदकर युवक की हत्या की थी। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था।

दिल्ली में लगातार हो रही हत्याओं से पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। जिन जगहों पर हत्याकांड हुए हैं, वहां के लोग सहमे हुए हैं। इस तरह खुलेआम हत्याओं की बात किसी को भी डरा सकती हैं।

शाहदरा में एक करोड़ की हेरोइन बरामद, तस्कर गिरफ्तार

नई दिल्ली। शाहदरा जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान रॉकी उर्फ प्रदीप (35) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से 282 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन बरामद की है। इसकी कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है। उसके पास से एक स्कूटी भी बरामद हुई है। पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा के मुताबिक, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सूचना मिली थी कि मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल एक आरोपित सीमापुरी स्थित दिल्ली जल बोर्ड के पास डियर पार्क इलाके में आने वाला है। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर घेराबंदी कर दी। कुछ देर बाद एक युवक स्कूटी से वहां पहुंचा। पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली तो उसके पास से एक पैकेट में 282 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने रॉकी उर्फ प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह यमुनापार के अलावा दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में हेरोइन की आपूर्ति करता है। शुरूआती जांच में पता चला है कि उसे बरेली से हेरोइन मिलती थी। आरोपित के मुताबिक, सीमापुरी में ही उसका सप्लायर उसे मादक पदार्थ उपलब्ध कराता था। पुलिस अब आरोपित के सप्लायर का पता लगाने में जुटी है। यह भी जांच की जा रही है कि बरेली से हेरोइन की खेप किसके जरिए सीमापुरी तक पहुंचती थी और इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, रॉकी के खिलाफ पहले से मादक पदार्थ तस्करी के चार मामले दर्ज हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में जन्माष्टमी से शुरू हुआ बारिश का दौर आज रविवार सुबह भी जारी है। नोएडा समेत एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। जिससे मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं, ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में शनिवार को दिनभर रुक-रुककर हुई तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। प्रमुख सड़कों और मार्गों पर जलभराव के कारण वाहनों की रफ्तार थम गई। कई जगह घुटनों तक पानी भर गया। दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़े मार्गों के अलावा पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में भी लोगों को जलभराव और जाम का सामना करना पड़ा। दिल्ली में शनिवार को बारिश का सबसे अधिक असर महिपालपुर और राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (एनएच-48) पर दिखाई दिया। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से धौला कुआं के बीच एनएच-48 पर पानी भरने से यातायात प्रभावित रहा। महिपालपुर में स्थिति गंभीर रही और कई वाहन पानी के बीच से गुजरते दिखाई दिए। टर्मिनल-3 के आसपास भी जलभराव हुआ। पालम एयरपोर्ट टनल, संगम विहार की नीम चौक रोड, शकरपुर, लक्ष्मी नगर और महरौली-बदरपुर रोड पर भी कई स्थानों पर पानी जमा रहा।

उधर, शनिवार को द्वारका में रोटरी चौक से डीजेबी चौक, डीजेबी रेड लाइट से ओमैक्स रोड तथा सेक्टर-1, 7, 8, 9, 10 और 20 से जुड़े मार्ग जलभराव से प्रभावित रहे। एनएच-8 अंडरपास में भी पानी भर गया। मथुरा रोड पर अपोलो अस्पताल और आश्रम चौक के बीच पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ।

हर्ष मल्होत्रा ने निगम शिक्षकों को किया सम्मानित

निगम श्री विद्यालय सहित तीन कार्यक्रमों की घोषणा की

नई दिल्ली। शिक्षक दिवस पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने शनिवार को केदारनाथ साहनी सभागार में निगम शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने छात्र जीवन के संस्मरण साझा किए एवं शिक्षकों को अपनी कक्षा के छात्रों के भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रेरित किया। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि शिक्षक के कंधों पर देश के भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी होती है। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि शिक्षक समाज एवं राष्ट्र को दिशा देने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे जो देश का भविष्य हैं उनके भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी भी शिक्षक की होती है। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति एवं शिक्षाविद् डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी याद किया। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आज का दिन केवल एक व्यक्ति के सम्मान का न होकर पूरी व्यवस्था एवं गुरु शिष्य परंपरा के सम्मान का दिन है। उन्होंने कहा कि आज का समय नई तकनीक एवं नए कौशल सीखने का समय है और सुनिश्चित करना है कि छात्र इस कार्य में किसी से भी पीछे न रहें।

इस अवसर पर दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि निजी विद्यालयों से हर मामले में बेहतर निगम विद्यालय के शिक्षक हैं। वाही ने कहा कि आज निगम विद्यालय पहले से काफी बेहतर स्थिति में हैं और विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं एवं स्मार्ट शिक्षकों को देखकर काफी अच्छा लगता है।

महापौर ने कहा कि दिल्ली में 20 से 21 लाख बच्चे 5-10 वर्ष की आयु के हैं और इनका 30 प्रतिशत छात्र निगम विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और इन बच्चों को अच्छी सुविधा एवं अच्छी शिक्षा देना निगम का दायित्व है। उन्होंने कहा कि निगम विद्यालय मेधावी शिक्षकों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे।

वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव 57 लाख नाम जुड़े

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 के बाद और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (रक्फ़) के नए चरण की शुरूआत से पहले देश के 17 राज्यों में मतदाता सूची में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है। एक विश्लेषण के अनुसार, इस अवधि में जहां करीब 57.57 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए, वहीं लगभग 5.57 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए।सिटी गाइड खोजें यह बदलाव उन 17 राज्यों में देखने को मिला है, जहां रक्फ़का तीसरा चरण चल रहा है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया चुनाव आयोग की नियमित समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा होती है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। विश्लेषण के अनुसार, अप्रैल-मई 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इन 17 राज्यों में कुल 35.50 करोड़ मतदाता दर्ज थे। इसके बाद साल के मध्य तक मतदाताओं की संख्या बढ़कर करीब 36.08 करोड़ हो गई।

इस तरह कुल मतदाता संख्या में लगभग 1.62 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, इस दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने से मतदाता सूची में बदलाव काफी व्यापक रहा। लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी रही। इस दौरान करीब 57.57 लाख नए मतदाताओं को सूची में शामिल किया गया।

नए मतदाताओं में ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने मतदान की निर्धारित आयु पूरी की हो या जिन्होंने पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया हो। इसके अलावा स्थान परिवर्तन के बाद नए क्षेत्रों में नाम जोड़ने वाले लोगों को भी सूची में शामिल किया जाता है।

वहीं, मतदाता सूची से 5.57 करोड़ नाम हटाए जाने का आंकड़ा सामने आया है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया के तहत मृत मतदाताओं, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोगों या डुप्लीकेट नामों को हटाया जाता है।

इसके अलावा ऐसे नाम भी हटाए जा सकते हैं जिनकी पुष्टि नहीं हो पाती या जिनके संबंध में सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी रक्फ़का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट करना और उसमें मौजूद गलतियों को दूर करना है।

चांद पर पहुंच गए, लेकिन हाथ से मैला ढोना खत्म नहीं हुआ

● बॉम्बे हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

मुंबई, एजेंसी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने देश में व्यापत एक ऐसी कुप्रथा की तरफ ध्यान देने के लिए कहा है जो सालों से चल रही है। हाई कोर्ट ने कहा कि हम चांद पर पहुंचने का दावा तो करते हैं, लेकिन अब तक हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म नहीं कर पाए। बॉम्बे HC ने कहा कि भारत चांद के अनछुए हिस्से तक पहुंचने का दावा तो करता है, लेकिन जाति व्यवस्था की आड़ में उसके कुछ नागरिक अब भी इंसानी गरिमा के खिलाफ काम करने को मजबूर हैं।

चांद पर पहुंचे, लेकिन हाथ से मैला ढोना खत्म नहीं: जस्टिस भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे ने कहा, '21वीं सदी में हम चांद के दूसरी तरफ पहुंचने का दावा करते हैं। फिर भी, कड़वी सच्चाई यह है कि हमारे देश में जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराई अब भी मौजूद है, जो हमारे कुछ नागरिकों को ऐसा काम करने के लिए मजबूर करती है जो इंसानी गरिमा के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने आगे कहा, 'हालांकि संविधान सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता और कानून का समान संरक्षण देता है, लेकिन संविधान को अपनाए हुए 75 साल बीत जाने के बाद भी हमारा देश उस सामाजिक बुराई से मुक्त नहीं हो पाया है जिसने हमें सदियों से परेशान कर रखा है।' हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी हाल ही में 'मैनुअल स्कैवेंजर्स के तौर पर रोजगार पर रोक और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013' को लागू करने में राज्य/स्थानीय अधिकारियों की विफलता के खिलाफ दायर याचिका पर की। हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को इस मामले में हुई सुनवाई के फैसले में ये बात कही, जिसे गुरुवार, 3 सितंबर को अपलोड किया गया।

सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है रोक: हाई कोर्ट ने कहा, 'हाथ से मैला ढोना एक ऐसी प्रथा है, जो समुदाय के एक खास वर्ग को पीढ़ियों से इस अमानवीय काम को करने के लिए मजबूर करती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों और कानूनों में इस पर रोक लगाई गई है।' सरकारी आदेशों में राज्य के फैसले को रद कर दिया और कहा कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर/सेक्टर द्वारा काम पर रखे गए जिन सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई, उनके परिवार राज्य सरकार से 30 लाख रुपये का मुआवजा पाने के हकदार होंगे (जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था), और राज्य यह रकम संबंधित नियोक्ताओं से वसूल सकता है।

बॉम्बे हाई कोर्ट में यह याचिका एक मजदूर यूनियन 'श्रमिक जनता संघ' से जुड़े राजू माधवे और लेखक श्रेयस पांडे के साथ मिलकर दायर की थी। राजू माधवे, सूरज के पिता थे, जिनकी 2022 में मुंब्रा की एक हाउसिंग सोसाइटी में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय मौत हो गई थी। सीनियर वकील गायत्री सिंह ने दलील दी कि तत्र में मुआवजा देने की जिम्मेदारी राज्य/स्थानीय अधिकारियों के बजाय प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर/नियोक्ताओं पर डाली गई थी। राज्य के वकील ने पहले कहा था कि 36 जिलों को हाथ से मैला उठाने की प्रथा (मैनुअल स्कैवेंजिंग) से मुक्त घोषित कर दिया गया है और अगस्त 2023 में कलेक्टरों ने इसके सर्टिफिकेट जमा कर दिए थे, लेकिन अगस्त 2024 की सुनवाई में उन्होंने कहा कि यह स्थिति सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख के हिसाब से थी। हाथ से मैला उठाने की प्रथा के जारी रहने के उदाहरण देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि रिकॉर्ड के उलट, राज्य ने 81 मामलों में 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया है। जजों ने कहा, 'इस तरह, यह नतीजा निकाला जा सकता है कि राज्य इस सामाजिक बुराई, यानी हाथ से मैला उठाने की प्रथा को पूरी तरह खत्म करने में सफल नहीं रहा है। हालांकि राज्य ने कुछ हद तक नियमों का पालन किया है, लेकिन यह देखकर दुख होता है कि राज्य की एजेंसियां आधे-अधूरे मन से कोशिशें कर रही हैं।' जजों ने सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले उन पांच मृत लोगों के आश्रितों को भी 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिनका मामला याचिकाकर्ताओं ने उठाया।

नोएडा एयरपोर्ट पर अनुमान से 8 गुना कम पहुंचे यात्री

● कार्गो सेवा पर लगा ब्रेक

ग्रेटर नोएडा , एजेंसी। उत्तर प्रदेश के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या शुरुआती अनुमान के मुकाबले आठ गुना तक कम है। 15 जून से 31 जुलाई तक एयरपोर्ट से कुल 97,115 यात्रियों ने सफर किया, जबकि अकेले जुलाई महीने में यह आंकड़ा 76,593 रहा। नोएडा एयरपोर्ट पर बीते 15 जून 2026 को यात्री विमान सेवा शुरू की गई थी। परिचालन के बाद यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन यह वृद्धि अनुमान की तुलना में काफी धीमी है। एयरपोर्ट शुरू होने से पहले हर महीने करीब छह लाख यात्रियों के सफर करने का अनुमान लगाया गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) द्वारा हाल में जारी आंकड़ों से संकेत मिल रहे हैं कि एयरपोर्ट के परिचालन में आगे और भी धीमी वृद्धि के आसार हैं। शुरुआती चरण में सीमित उड़ानों को यात्री संख्या कम रहने की प्रमुख वजह माना जा रहा है। हालांकि, आने वाले समय में नई उड़ानें और नए रूट जुड़ने पर यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। एयरपोर्ट से फिलहाल 15 शहरों के लिए उड़ानें मिल रही हैं। प्रतिदिन रनवे से 32 विमान लैंड और टेकऑफ कर रहे हैं। एयरपोर्ट से अभी सिर्फ घरेलू उड़ानें ही शुरू हो पाई हैं। फिलहाल, अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल का कार्य निर्माणाधीन है। अधिकारियों का दावा है कि यह काम नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। इसी वर्ष अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में उड़ान शुरू होने से यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

कार्गो सेवा भी नहीं उड़ी: नोएडा एयरपोर्ट को शुरू हुए करीब ढाई महीना बीत चुका है। 17 जून को पहली कार्गो फ्लाइट चेन्नई से उड़ान भरकर नोएडा पहुंची थी। इसके बाद से एयरपोर्ट से दूसरी कोई कार्गो फ्लाइट नहीं उड़ी है। पिछले दिनों कार्गो बनाने वाली कंपनी ने पशुओं के आवागमन को लेकर भी दो कंपनियों के साथ समझौता किया था। फिलहाल इससे जुड़ी भी कोई कार्गो फ्लाइट नहीं उड़ पाई है।

पहली यात्री उड़ान में किसानों ने किया था सफर: गौरतलब है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून को लखनऊ के लिए रवाना हुई पहली उड़ान सिर्फ यात्री सेवा की शुरुआत नहीं थी, बल्कि जेवर के उन किसानों के लिए भावनात्मक पल भी बन गई थी, जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीनें दी थी। इस ऐतिहासिक उड़ान में यात्री बनकर पहुंचे किसान लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर उतरे तो चेहरों पर गर्व, खुशी और आंखों में नमी साफ दिखी। किसानों ने साफ कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने उनके गांवों को नई पहचान दी है और सीएम योगी ने वादा निभाकर उनके सपनों को साकार किया है। एयरपोर्ट से आने वाली पीढ़ियों को नए अवसर मिलेंगे।

तेलंगाना में किडनैप-मर्डर केस का आरोपी बरी, सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में तीसरी बार पलटा निचली अदालत का फैसला

हैदराबाद, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के तेलंगाना अपहरण और हत्या के एक चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की पीठ ने सबूतों के विश्लेषण पर सवाल उठाते हुए आरोपी की सजा और दोषसिद्धि को रद कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीड़ित का शव फ्रिज से बरामद होने और पोस्टमार्टम में गला घोंटने की पुष्टि के बावजूद, आरोपी को सीधे इस अपराध या फ्लैट से जोड़ने वाला कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत मौजूद नहीं है। धनंजय महापात्रा की रिपोर्ट के अनुसार, एक हफ्ते में तीसरी बार निचली अदालत का फैसला पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराए गए आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला: दरअसल, साल 2012 में तेलंगाना में एक व्यक्ति का किडनैप किया गया था। किडनैपर्स ने 23 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी, जिसमें से पीड़ित के पिता ने 1.5 लाख रुपये दिए भी थे। इसके बावजूद पीड़ित की हत्या कर दी गई। आरोपियों की निशानदेही पर एक फ्लैट में रखे रेफ्रिजरेटर (फ्रिज) से उसका शव बरामद हुआ। ट्रायल कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि तेलंगाना हाईकोर्ट ने चार को बरी कर दिया और एक की सजा बरकरार रखी थी।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने पाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किए जाने और शव फ्रिज में मिलने की पुष्टि तो होती है, लेकिन आरोपियों को इस अपराध या उस फ्लैट से जोड़ने वाला कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ शव की बरामदगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर किसी को हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ठोस सबूत न होने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने पांचवे आरोपी को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी कर दिया।

चिलिमे सुरंग में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान, भारतीय टीम जुटी; मृतकों का आंकड़ा 1344 पहुंचा

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल में बाढ़ के बाद हालात बदतर बने हुए हैं। हर दिन के साथ हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि अभी भी हजारों लोग लापता हैं। वहीं, इस भीषण त्रासदी को झेलने वाले अब मानसिक रूप से पीड़ा झेल रहे हैं, जिसमें बच्चे से लेकर बड़े भी शामिल है। नेपाल के दार्चुला जिले में शुक्रवार को भारी भूस्खलन के बाद चौलानी नदी का प्रवाह बाधित हो गया। नदी का रास्ता बंद होने से आसपास के क्षेत्रों में खतरा बढ़ गया है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। लोगों को नदी के आसपास और निचले क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

चिलिमे सुरंग में भारतीय टीम क्या कर रही है: भारतीय सुरंग बचाव दल ने शुक्रवार को चिलिमे सुरंग के अंदर अभियान चलाया। टीम का प्रयास सुरंग के पानी और मलबे से प्रभावित हिस्सों तक पहुंचने और वहां फंसे लोगों की तलाश करने का है। भारी उपकरणों को सुरंग तक पहुंचाने और बचाव अभियान को गति देने के लिए एक अस्थायी ट्रैक भी तैयार किया जा रहा है। टीम ने सुरंग के भीतर सुरक्षा रस्सियां लगाई हैं, जबकि पानी और मलबे से बाधित हिस्सों में फ्लोट और पंप भी तैनात किए जा रहे हैं। रसुवा जिले के स्याब्रुबेसी गांव के पास स्थित चिलिमे जलविद्युत परियोजना का इलाका बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ था।

सुरंग के कई हिस्से पानी और मलबे से बाधित हो गए थे, जिसके कारण वहां पहुंचना चुनौतीपूर्ण बना हुआ था। अब भारतीय टीम सुरंग के अंदर आगे बढ़कर प्रभावित हिस्सों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, ताकि खोज और बचाव अभियान को और प्रभावी बनाया जा सके। नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। भारतीय बचाव दल नेपाली अधिकारियों के साथ मिलकर प्रभावित इलाकों में खोज, बचाव और राहत कार्यों में जुटा है। इसी क्रम में विशेष भारतीय सुरंग बचाव टीम ने चिलिमे सुरंग में अभियान तेज कर दिया है। वहीं शुक्रवार को नेपाल सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि बाढ़ से 32 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इससे सड़कें, पुल, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों को नुकसान पहुंचा है। सरकार की शुरुआती रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। वहीं इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 1344 हो गई। प्रभावित इलाकों से और शव मिलने के बाद मृतकों की संख्या बढ़ी है।

मॉस्को जाने पर गिरफ्तारी का खतरा, फिर भी तैयार थे जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ बुदानोव

कीव, एजेंसी। इस वर्ष के शुरू में में जब शांति वार्ता का एक दौर खत्म हुआ, तो यूक्रेनी वार्ताकारों को रूसियों की तरफ से एक हैरान करने वाला प्रस्ताव मिला। इसमें कहा गया कि यूक्रेनी अधिकारी चाहें तो मॉस्को की उड़ान पकड़ सकते हैं और वार्ता जारी रख सकते हैं। इसका फायदा यह था कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की संभावना थी और नुकसान यह था कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता था, या उससे भी बुरा कुछ हो सकता था। प्रस्ताव ने इससे पहले जिनेवा में वार्ता के दौरान यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले किरीलो बुदानोव के सामने एक गंभीर असमंजस उत्पन्न कर दिया। रूस ने उन पर आतंकवाद के आरोप लगा रखे हैं, जो तब लगाए गए थे जब वह यूक्रेन के सैन्य जासूसी प्रमुख थे। लेकिन वार्ता के माध्यम से शांति हासिल करने के लिए वह कोई भी अप्रत्याशित कदम उठाने के लिए तैयार थे। कभी रूस से डटकर मुकाबला करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल बुदानोव मौजूदा समय में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ हैं और किसी भी कीमत पर शांति चाहते हैं। बुदानोव का कहना है, बातचीत आज नहीं तो कल किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेगी। आप पूरी जिंदगी युद्ध नहीं लड़ सकते। यूक्रेनी सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले बुदानोव ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं युद्ध खत्म करने वाले किसी भी कदम के लिए तैयार हूं। बशर्ते यूक्रेन को इसकी शर्तें मंजूर हों। उन्होंने मॉस्को दौरे के प्रस्ताव के बारे में खुलासा किया, जिसकी रिपोर्ट पहले सामने नहीं आई थी। यही नहीं यह दौरान भी परवान नहीं चढ़ सका था, और आगे बातचीत ठप हो गई थी।

वार्ता फिर शुरू होने की उम्मीद : जंग लगातार जारी रहने के बीच बुदानोव ने सितंबर के आखिर तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में शांति वार्ता फिर शुरू होने की उम्मीद जताई है। विश्लेषकों का कहना है, शांति की पहल की बुदानोव की मंशा उनके व्यक्तित्व के दो अलग पहलुओं को सामने लाती है। वह एक ऐसे सैनिक के तौर पर अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं जिसने रूस के खिलाफ जमकर जंग लड़ी।

पूर्वी यूक्रेन में 2014 में लंबे समय से सुलगते रहे युद्ध के दौरान बुदानोव ने दुश्मन की सीमा के पीछे जाकर कमांडो छापों का नेतृत्व किया था।

सऊदी अरब को अमेरिका की सौगात पांच अरब डॉलर के हथियार सौदे को मंजूरी; जेडीएएम किट-बमों से खाड़ी में बढ़ेगी ताकत

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिका ने सऊदी अरब को करीब 5 अरब डॉलर के हथियार और सैन्य उपकरण बेचने की संभावित डील को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित बिक्री में सटीक निशाना लगाने वाली जेडीएएम-ईआर प्रणालियां, हजारों बम और उनसे जुड़े उपकरण शामिल हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने इसकी जानकारी कांग्रेस को दी है।

प्रस्तावित हथियार सौदे में क्या-क्या शामिल है: अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, सऊदी अरब ने 5,004 केएमयू-572 जेडीएएम गाइडेंस किट और 5,000 केएमयू-556 जेडीएएम गाइडेंस किट की मांग की है। इसके अलावा 5,004 बीएलयू-111 500-पाउंड सामान्य उपयोग वाले बम और 5,000 बीएलयू-117 2,000-पाउंड बम भी प्रस्तावित पैकेज का हिस्सा हैं। डील में फ्यूज सिस्टम, टारगेट डिटेक्टर, कंटेनर, स्पेयर पार्ट्स, सपोर्ट उपकरण और अन्य जरूरी सामान भी शामिल होंगे। इसके साथ अमेरिकी सरकार और ठेकेदारों की इंजीनियरिंग, तकनीकी और लॉजिस्टिक सेवाएं भी प्रस्तावित हैं।

अमेरिका सऊदी अरब को ये हथियार क्यों देना चाहता है: अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि इस संभावित बिक्री से सऊदी अरब की सुरक्षा मजबूत होगी और खाड़ी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता तथा आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका के मुताबिक, इससे सऊदी अरब की मौजूदा और भविष्य की क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने की क्षमता बेहतर होगी। विभाग ने कहा कि इससे सऊदी अरब की अपनी जमीन की रक्षा करने की क्षमता बढ़ेगी और अमेरिकी तथा खाड़ी क्षेत्र के सहयोगी देशों की सेनाओं के साथ उसकी सैन्य प्रणालियों की बेहतर तालमेल क्षमता विकसित होगी।

क्या इस सौदे से क्षेत्र का सैन्य संतुलन बदलेगा: अमेरिकी आकलन के मुताबिक, प्रस्तावित लेनदेन से क्षेत्रीय सैन्य संतुलन में कोई बदलाव नहीं होगा। अमेरिका का यह भी कहना है कि सऊदी अरब इन हथियारों और सेवाओं को अपनी सैन्य व्यवस्था में आसानी से शामिल कर सकेगा। इस संभावित बिक्री के लिए मुख्य ठेकेदार बोइंग होगा, जिसका मुख्यालय वर्जीनिया में है। अमेरिकी सरकार ने कहा कि फिलहाल इस सौदे के साथ किसी ऑफसेट समझौते की जानकारी नहीं है।

क्या इस हथियार सौदे का पश्चिम एशिया के तनाव से भी संबंध है: यह संभावित हथियार सौदा ऐसे समय सामने आया है, जब पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं। क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष, सऊदी अरब को निशाना बनाकर हुए हमलों और यमन के हूती विद्रोहियों की गतिविधियों ने खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई है।

ऐसे माहौल में सऊदी अरब अपनी जमीन और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को संभावित हवाई तथा मिसाइल खतरों से बचाने की क्षमता मजबूत करना चाहता है।

क्या अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते सिर्फ रक्षा तक सीमित हैं: अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हालिया सहयोग केवल रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। एक महीने से ज्यादा समय पहले दोनों देशों ने शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग के लिए भी समझौते किए थे।

अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट और सऊदी ऊर्जा मंत्री अब्दुलअजीज बिन सलमान ने शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसे आम तौर पर '123 समझौता' कहा जाता है। इसके साथ द्विपक्षीय सुरक्षा उपायों से जुड़ा समझौता भी हुआ था। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के मुताबिक, 123 समझौता से अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब के उभरते नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में ज्यादा पहुंच मिल सकती है।

इसके साथ अमेरिकी उद्योग, कामगारों और सप्लाई चेन को भी लाभ पहुंचाने की बात कही गई है। दोनों समझौते परमाणु सुरक्षा, सुरक्षा मानकों और परमाणु अप्रसार को मजबूत करने के साथ अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए आधार तैयार करते हैं।

रूस-यूक्रेन जंग में बढ़ी हलचल कीव के बाद मॉस्को भी जाएंगे अमेरिकी दूत

कीव, एजेंसी। अमेरिका के अधिकारी स्टीव विटकॉफ और जरेड कुशनर इस सप्ताहांत मॉस्को जाएंगे। इसके बाद वे कीव जाएंगे। उनका दौरा अगले सप्ताह की शुरुआत तक चल सकता है। अमेरिका के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। वह अधिकारी सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं था। इसलिए उसने नाम न बताने की शर्त पर बात की। अधिकारी ने दोनों जगहों पर जाने के सही समय की जानकारी नहीं दी। यह दोनों अमेरिकी अधिकारियों की कीव की पहली यात्रा होगी। अमेरिका युद्ध खत्म कराने के लिए बातचीत की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब तक इन कोशिशों से शांति का रास्ता नहीं निकल पाया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि वह विटकॉफ और कुशनर के रविवार को कीव पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। इससे पहले दोनों अधिकारी मॉस्को जाएंगे। जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर कहा कि बातचीत के दौरान यूक्रेन हवाई हमले नहीं करेगा। उन्होंने रूस से भी ऐसा ही करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे बातचीत सुरक्षित तरीके से हो सकेगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, अमेरिकी पक्ष की पिछली राजनयिक यात्राओं की तरह हम यह सुनिश्चित करेंगे कि रूसी हवाई क्षेत्र सामान्य रूप से काम करता रहे, ताकि बातचीत के लिए आने वाले अधिकारी सुरक्षित पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को उनकी सुरक्षा की चिंता है। रूस की नहीं। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शुक्रवार को अमेरिकी अधिकारियों के मॉस्को दौरे की खबरों की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई बैठक होती है, तो मीडिया को इसकी जानकारी दी जाएगी। कुशनर और विटकॉफ इससे पहले जनवरी में मॉस्को गए थे।

संक्षिप्त समाचार

बेंगलुरु में बड़ी कार्रवाई, खरगे की रैली के बाद शुद्धिकरण को लेकर उत्तराखंड भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज

बेंगलुरु, एजेंसी। बेंगलुरु में उत्तराखंड भाजपा सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ एक 'जीरो एफआईआर' दर्ज की गई। यह मामला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद एक जगह पर कथित 'शुद्धिकरण' किए जाने से जुड़ा है।द्य एक अधिकारी ने बताया कि यह मामला 31 अगस्त को विधान सौधा पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के एसटी विभाग के पूर्व उपाध्यक्ष टीआर रामप्पा की शिकायत पर दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि 'जीरो एफआइआर' एक ऐसा मामला है जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा सकता है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो या पुलिस स्टेशन का अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता ने बताया कि आठ अगस्त को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित रामलीला मैदान में एक बड़ी जनसभा में हिस्सा लिया और उसे संबोधित किया। जनसभा के बाद भाजपा के कुछ सदस्यों और पदाधिकारियों ने कथित तौर पर 10 अगस्त को उसी जगह पर एक तथाकथित 'शुद्धिकरण अनुष्ठान' आयोजित किया। आरोप लगाया गया है कि इस अनुष्ठान का उद्देश्य कथित तौर आपत्तिजनक, अपमानजनक और जातिवादी सोच दिखाना था कि अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य मल्लिकार्जुन खरगे की मौजूदगी ने उस जगह को 'अशुद्ध' कर दिया था। इसलिए उस जगह को अनुष्ठान के जरिये शुद्ध करने की जरूरत थी।

त्रिपुरा में हथियार डाल चुके उग्रवादी समूहों ने नहीं मानी बात, 72 घंटे का जाम शुरू

अगरतला, एजेंसी। त्रिपुरा में हथियार डाल चुके सात उग्रवादी समूहों ने शुक्रवार को 11 मांगों को पूरा करवाने के लिए असम-अगरतला नेशनल हाईवे पर 72 घंटे का जाम शुरू कर दिया है। उन्होंने त्रिपुरा सरकार की उस अपील को ठुकरा दिया, जिसमें उनसे अपनी मांगें पूरी होने तक सड़क और रेल मार्ग की नाकेबंदी हटाने को कहा गया था। नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा (ओरिजिनल), एनएलएफटी (परिमाल देबबर्मा), आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, एनएलएफटी (नयन बाशी), ज्वाइंट एक्शन रिहैबिलिटेशन कमिटी, ज्वाइंट एक्शन कमिटी और आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ओल्ड) के सदस्यों और समर्थकों ने अपने पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार सुबह जाम शुरू किया। प्रदर्शनकारी बारामुरा के चंद्र साधुपदा इलाके में जमा हुए और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान टायर भी जलाए गए, जिससे गाड़ियों की आवाजाही लगभग ठप हो गई और बड़ी संख्या में गाड़ियां अलग-अलग जगहों पर फंसी रह गई। एनएलएफटी नेता थामस त्रिपुरा ने कहा कि ये समूह लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और दावा किया कि केंद्र और त्रिपुरा सरकार के साथ हुए कई समझौतों को लागू नहीं किया गया है।

असम में 1.4 करोड़ रुपये की याबा टैबलेट और म्यांमार की सिगरेट जब्त, सात गिरफ्तार

गुवाहाटी, एजेंसी। असम में अलग-अलग अभियानों के दौरान 1.4 करोड़ रुपये की याबा टैबलेट और 1.2 लाख से अधिक म्यांमार की सिगरेट के साथ सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया याबा टैबलेट्स श्रीभूमि जिले में जब्त की गई, वहीं तस्करी की गई सिगरेट कछार जिले में जब्त की गई। याबा टैबलेट मादक पदार्थ होता है। इस पर भारत में प्रतिबंध है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कहा, पुलिस ने दो वाहनों को रोका और 14 हजार याबा टैबलेट्स जब्त कीं, जिनकी कीमत 1.4 करोड़ रुपये है। पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इंटरनेट मीडिया पोस्ट में बताया कि कछार जिले में एक और अभियान चलाया गया। पुलिस ने असम-मेघालय सीमा पर डिगोर्कहाल चेक पोस्ट पर एक वाहन को रोका और छिपाई गई 1,20,000 बर्मीज सिगरेटें जब्त कीं। इस मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

दैनिक प्रभात परिक्रमा

भोपाल, सोमवार 7 सितंबर 2026

उप मुख्यमंत्री यादव महासभा के श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में हुए शामिल

श्रीकृष्ण के प्रसंग पर्यावरण संरक्षण, जीव-दया और सामूहिक सुरक्षा का देते हैं संदेश : उप मुख्यमंत्री

नगर प्रतिनिधि | भोपाल

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल जन्माष्टमी पर्व के पावन अवसर पर कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा द्वारा आयोजित श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम मे समाज के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 12 बजे रात्रि आराध्य देव श्री कृष्ण के जन्म उपरांत पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में उप मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीकृष्ण के जीवन चरित्र, उनकी लीलाओं तथा श्रीमद्भगवद्गीता के सार्वभौमिक संदेशों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने समाज को अधर्म और दुष्ट प्रवृत्तियों से बचाने के लिए सतर्कता, धैर्य, कूटनीति और नैतिक संकल्प शक्ति अपनाने का आह्वान किया। इतिहास और पौराणिक कालखंडों का उल्लेख करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज में नकारात्मक एवं उपद्रवी तत्वों की उपस्थिति केवल वर्तमान कलयुग तक सीमित नहीं है, बल्कि द्वापर और त्रेता युग में भी ऐसे तत्व विद्यमान थे।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि द्वापर युग में शिशुपाल जैसे लोग मौजूद थे, जो मर्यादा की सीमाओं को लांघने और व्यवस्था को क्षति पहुँचाने के लिए आतुर रहते थे। वर्तमान कलयुग में भी जब इस प्रकार के उपद्रवी लोगों का सामना होता है, तो समाज को हताश या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह समाज का नैतिक दायित्व है कि वह ऐसे तत्वों की पहचान करे, उन्हें समाज से किनारे करे और समय आने पर धर्म एवं न्याय की रक्षा हेतु उन्हें पूर्णतः परास्त भी करे। यही भगवान श्रीकृष्ण के जीवन मूल्यों और आदर्शों को व्यवहार में उतारने का सच्चा मार्ग है। उप मुख्यमंत्री ने मानव जीवन के वास्तविक पथ-प्रदर्शन हेतु श्रीमद्भगवद्गीता के अमर ज्ञान को केंद्र में रखते हुए कहा कि चाहे रामलीला हो या कृष्णलीला, ये केवल कथाएँ नहीं हैं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले जीवंत माध्यम हैं। ये लीलाएँ सिखाती हैं कि विषम परिस्थितियों में भी एक धर्मनिष्ठ जीवन कैसे जिया जाए। इस अवसर पर उन्होंने गीता के निष्काम कर्मयोग की पंक्तियों का स्मरण कराते हुए कहा कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान।

लोक-कल्याण और अधर्म के नाश के लिए भगवान श्रीकृष्ण द्वारा उठाए गए कदमों का स्मरण कराते हुए श्री शुक्ल ने कहा कि बाल्यकाल से ही भगवान श्रीकृष्ण ने जन-सामान्य को अत्याचार से मुक्ति दिलाने का कार्य आरंभ कर दिया था।

कंस के क्रूर अत्याचारों को समाप्त करने के लिए कंस वध, कालिया नाग का दमन तथा देवराज इंद्र के अहंकार को चूर कर मूसलाधार वर्षा से ब्रजवासियों एवं गौ-माताओं की प्राण-रक्षा हेतु विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करना, ये सभी प्रसंग पर्यावरण संरक्षण, जीव-दया और सामूहिक सुरक्षा का अद्वितीय संदेश देते हैं।

अंत में उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने उपस्थित जनसमूह का आह्वान किया कि वे भगवान श्रीकृष्ण के जीवन-दर्शन से प्रेरणा लेकर समाज को संगठित, जागरूक और धर्मनिष्ठ बनाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि जब तक समाज अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं होगा और शांति की पहल के साथ-साथ अधर्म के प्रतिकार का साहस नहीं रखेगा, तब तक एक समरस और सुरक्षित समाज का निर्माण संभव नहीं है। समारोह में सांसद श्री जनार्दन मिश्र, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी , अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष सखाराम यादव, सीएल यादव, संगीता राजेश यादव, राकेश यादव, डॉ. सुरेंद्र यादव, डॉक्टर शंकर लाल यादव, राम नरेश यादव, मनोज यादव, रेनू यादव, सूरज यादव, अवनीश यादव, दिलीप यादव, अशोक यादव, राजबहोर यादव, डॉ. शब्द सिंह यादव, राम कुशल यादव सहित यादव महासभा के अन्य प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन रहे सजग

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी जिलों के कलेक्टर को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारी बारिश की संभावित परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम तैयारियां करने तथा आवश्यक संसाधनों को पहले से जुटाकर अमले को तैनात रखने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश की चेतावनी, विशेष रूप से उत्तरी मध्यप्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह सतर्क एवं मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसी भी संभावित समस्या की स्थिति से निपटने के लिए राहत एवं बचाव संसाधनों की उपलब्धता पहले से ही सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही जनहित और आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक और एहतियाती कदम अविलंब उठाए जाएं।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की संकल्प पूर्ति में अग्रणी भूमिका निभाएगा मप्र

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' के माध्यम से देश को इस क्षेत्र में सशक्त बनाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस संकल्प को साकार करने में मध्यप्रदेश अपनी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर जैसे आधुनिक विज्ञान के अनेक प्रकल्पों पर बेहतरीन काम हो रहा है। इस क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार अग्रसर है। एक दौर वो था, जब चिप निर्माण के दिशा में कोई सोचता भी नहीं था। अब मध्यप्रदेश ने इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए ठोस निर्णय लिए हैं।मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आगामी 23-24 अक्टूबर को इंदौर में होने वाली एमपी सेमीकंडक्टर समिट-2026 के कैम्पेन पोस्टर के विमोचन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. मोहन नागर, प्रमुख सचिव विज्ञान प्रौद्योगिकी श्री एम. सेल्वेन्द्रम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार अगले महीने 23-24 अक्टूबर को इंदौर में 'मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर समिट 2026' का आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस ग्लोबल समिट में शामिल हो जा रहे सभी निवेशकों, तकनीकी विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और नीति-निर्धारकों का मध्यप्रदेश की धरती पर स्वागत करते हुए उन्हें आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी देश-प्रदेशवासियों से एकजुट होकर सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर होने के स्वप्न को साकार करने और विज़न 2047 के समृद्ध मध्यप्रदेश एवं विकसित भारत की यात्रा में सहभागी होने का आह्वान किया।

मध्यप्रदेश पुलिस की सतर्कता और तकनीकी साक्ष्यों से धोखाधड़ी का पर्दाफाश

भोपाल ।प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा नागरिकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में राजगढ़ जिले के थाना पचोर पुलिस ने करेंसी एक्सचेंज के नाम पर 05 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 02 लाख 40 हजार रुपये नगद जब्त किए हैं।

पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री अमित तोलानी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री के.एल. बंजारे के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी सारंगपुर श्री अरविन्द सिंह के पर्यवेक्षण में थाना पचोर पुलिस टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई।25 अगस्त को सारंगपुर निवासी फरियादी द्वारा थाना पचोर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि एक महिला एवं दो पुरुषों द्वारा पचोर मंडी में करेंसी एक्सचेंज के नाम पर छल-कपटपूर्वक उसके साथ 05 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पचोर में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

लालघाटी अग्रवाल समाज ने की जजमानी, बड़ी संख्या में समाजजन हुए शामिल

भगवान अग्रसेन जी की 30वीं महाआरती संपन्न

नगर प्रतिनिधि | भोपाल

अग्रवाल समाज द्वारा अग्रकुल प्रवर्तक भगवान अग्रसेन महाराज एवं कुलदेवी माता महालक्ष्मी की नियमित महाआरती के क्रम में रविवार को अग्रसेन वाटिका, आईटीसी पार्क, कमला पार्क के सामने 30वीं महाआरती श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुई। महाआरती की जजमानी इस अवसर पर लालघाटी अग्रवाल समाज द्वारा की गई। महाआरती में अग्रवाल समाज के बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। विधि-विधान से पूजा-अर्चना के पश्चात भगवान अग्रसेन महाराज की महाआरती की गई। इस दौरान पूरा परिसर जयकारों और भक्ति भाव से गूंज उठा। आयोजक नितिन गुप्ता और मुकेश गोयल ने बताया कि माह के प्रथम रविवार को आयोजित होने वाली यह नियमित महाआरती सुचारु रूप से जारी है और समाज को एकजुट करने तथा भगवान अग्रसेन महाराज के आदर्शों एवं सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बन रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही नगर निगम से संपर्क कर शेड निर्माण की प्रक्रिया के लिए अनुमति ली जाएगी, जिसके बाद शेड का निर्माण कराया जाएगा। इस अवसर पर समाजजनों ने भगवान अग्रसेन महाराज के 'एक ईंट, एक रुपया' के संदेश को स्मरण करते हुए सामाजिक सहयोग, एकता और सेवा की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आयोजकों ने महाआरती में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी समाजजनों का आभार व्यक्त किया।

प्रदेश में फिर झमाझम का अलर्ट 19 जिलों में भारी बारिश, ग्वालियर-चंबल के 6 जिलों में स्कूल बंद

भोपाल।मध्यप्रदेश में मानसून का असर अब उत्तर और मध्य हिस्से में ज्यादा दिखाई देगा। पूर्वी हिस्से में लगातार बारिश के बाद सक्रिय हुआ मौसमी तंत्र अब ग्वालियर-चंबल की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने शनिवार को 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। श्योपुर और शिवपुरी में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, सागर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, आगर-मालवा और मंदसौर में भारी बारिश हो सकती है। **ग्वालियर-चंबल में अगले दो दिन ज्यादा असर :**मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मौसमी तंत्र का असर 5 और 6 सितंबर को ग्वालियर-चंबल, सागर और उज्जैन संभाग के कई जिलों में रहेगा। इसके बाद 7 और 8 सितंबर को भी कुछ इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। हालांकि इंदौर में इस दौरान तेज बारिश की संभावना कम है।

बारिश के कारण 7 जिलों में स्कूल बंद : लगातार बारिश और कई जगह बने बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए 5 सितंबर को कई जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है।मुरैना में सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद हैं। श्योपुर में नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। शिवपुरी में सभी शैक्षणिक संस्थान और आंगनवाड़ी केंद्र बंद हैं। गुना में नर्सरी से 12वीं तक स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद किए गए हैं। भिंड में नर्सरी से 8वीं तक छुट्टी है। जबकि ग्वालियर में नर्सरी से 8वीं तक छुट्टी कर दी गई है। वही रायसेन में सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद की घोषणा की गई है।

पश्चिमी हिस्से में बारिश की कमी बरकरार :पश्चिमी हिस्से के कई जिलों में मानसून अभी भी औसत से पीछे है। आगर-मालवा, आलीराजपुर, अशोकनगर, बैतूल, देवास, धार, हरदा, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नर्मदापुरम, नीमच, बड़वानी, रायसेन, रतलाम, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन और विदिशा में सामान्य से 5 से 54 प्रतिशत तक कम बारिश हुई है।

अब वैज्ञानिक तरीके से तय होगी बड़े तालाब की हद

एनजीटी के निर्देश पर आज से काम शुरू, 7 विभागों के विशेषज्ञ तैनात

भोपाल, नप्र। बड़े तालाब की सीमा को लेकर वर्षों से चल रहे सर्वे और सीमांकन के खेल के बीच अब प्रशासन वैज्ञानिक तरीके से इसकी वास्तविक हद तय करने जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर भोज वेटलैंड, कलियासोत और केरवा जलाशयों के सीमांकन की शुरुआत शनिवार को भदभदा से होगी। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के साथ हुई बैठक में सर्वे की रूपरेखा तय की गई है।

भदभदा से होगी शुरुआत :शनिवार सुबह नौ बजे एनजीटी कमेटी, पर्यावरण विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में ड्रोन मैपिंग शुरू होगी। जानकारी के अनुसार भदभदा को शुरुआती केंद्र इसलिए चुना गया है, क्योंकि यहां से पानी कलियासोत में जाता है। सर्वे में

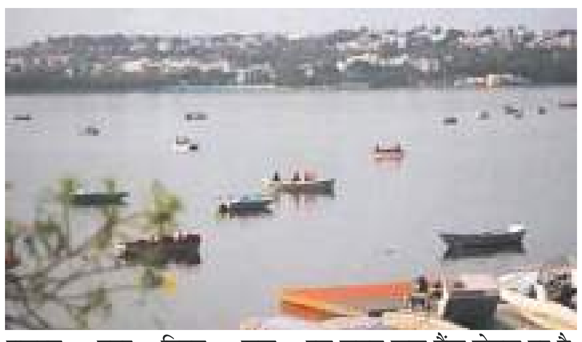

राजस्व, नगर निगम, जल संसाधन, वन विभाग, एमपीपीसीबी सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल रहेंगे।

नो फ्लाई जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मिल चुकी है। सर्वे में आधुनिक ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग, जियो-टैगिंग, पुराने मुनार-पिलर, वीडियोग्राफी और ग्राउंड ट्रुथिंग का इस्तेमाल होगा। तालाब इस समय फुल टैंक लेवल पर है, इसलिए जलस्तर के आधार पर वास्तविक सीमा का सटीक आकलन किया जाएगा।

2017 से जांचेंगे अतिक्रमण : इस बार अवैध निर्माणों की जांच वेटलैंड रूल्स-2022 नहीं, बल्कि 2017 के नियमों के आधार पर होगी। नई सीमा तय होने के बाद शहरी क्षेत्र में एफटीएल से 50 मीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 250 मीटर तक स्थायी-अस्थायी निर्माण प्रतिबंधित रहेगा। वेटलैंड, बफर और प्रभाव क्षेत्र में नियम विरुद्ध निर्माणों को तीन माह में हटाने की कार्रवाई होगी।

सात विभाग तय करेंगे तालाब की हद

एनजीटी की कमेटी में पर्यावरण मंत्रालय, सीपीसीबी, मैनिट, वन विभाग, राज्य वेटलैंड अथारिटी, जल संसाधन विभाग और एमपीपीसीबी के विशेषज्ञ शामिल हैं। एमपीपीसीबी नोडल एजेंसी रहेगी। वहीं, नियम विरुद्ध निर्माण की अनुमति देने या रोकने में नाकाम अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।

जल जीवन मिशन पर बड़ा खुलासा

मप्र की 155 पानी टेस्टिंग लैब में से एक में भी केमिकल जांच की व्यवस्था नहीं

भोपाल, नप्र। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ पानी की गुणवत्ता जांच की व्यवस्था को लेकर गंभीर कमियां उजागर हुई हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में संचालित सभी 155 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं में से एक में भी पानी में रासायनिक विषाक्तता (केमिकल टॉक्सिसिटी) जांचने की व्यवस्था मौजूद नहीं है। हालांकि, इन प्रयोगशालाओं में बैक्टीरिया व वायरस जैसे सूक्ष्मजीवीय संदूषण (माइक्रोबायोलॉजिकल कंटैमिनेशन) की जांच की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का परीक्षण करने की सुविधा प्रदेश की केवल एक राज्य-स्तरीय प्रयोगशाला तक सीमित है। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया, जिस पर केंद्र सरकार ने पेयजल व्यवस्था को राज्य का विषय करार दिया। सांसद तन्खा ने दस्तावेजों के साथ राज्य सरकार को पत्र लिखकर विस्तृत जांच और सुधार की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के 77.21त्न घरों में नल कनेक्शन चालू हैं।

मप्र में कहीं एक टीचर के भरोसे 51 बच्चे तो कहीं 212 पर 25 गुरुजी तैनात

भोपाल, नप्र। एक तरफ कई सरकारी स्कूलों में एक ही शिक्षक के कंधों पर पढ़ाई कराने के साथ-साथ मध्याह्न भोजन प्रबंधन, यू-डाइस प्रविष्टि, समग्र आईडी पोर्टल अपडेट और बच्चों को स्कूल लाने जैसे प्रशासनिक कार्यों का बोझ है। वहीं दूसरी तरफ, दर्जनों बच्चे वाले कुछ स्कूलों में शिक्षकों का बड़ा जमावड़ा मौजूद है। इस प्रशासनिक लापरवाही और असंतुलित पदस्थापना के कारण दर्जनों स्कूल बंद होने की कगार पर हैं या अतिथि शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं। कई स्थानों पर जर्जर भवनों के कारण बच्चे मंदिरों के प्रांगण में या पेड़ों की छांव में बैठने को मजबूर हैं।

भोपाल के दो स्कूलों से उजागर हुई अव्यवस्था :इनायतपुर प्राथमिक स्कूल- यहां 51 विद्यार्थियों को संभालने के लिए सिर्फ एक महिला शिक्षक हैं। शिक्षक के सेवानिवृत्त होने के बाद से नई पदस्थापना नहीं हुई, जिससे पहली से पांचवीं कक्षा तक के सभी बच्चे सीलन भरे एक ही कमरे में टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं।

नूतन सुभाष स्कूल- जर्जर भवन टूटने के कारण दूसरी जगह शिफ्ट हुए इस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 1200 से घटकर 212 रह गई है, लेकिन यहां 25 शिक्षक तैनात हैं। इसके बावजूद जगह की कमी के कारण 5वीं से 8वीं तक के छात्र एक ही कमरे में बैठते हैं।

अन्य जिलों से बदहाली की तस्वीरें :इंदौर के महू-मानपुर मार्ग पर कवच संस्था ने झुग्गी-झोपड़ी के 40 से अधिक बच्चों के लिए बांस-बल्लियों और ग्रीन नेट की मदद से एक अस्थायी पाठशाला शुरू की, जिससे प्रेरित होकर कई बच्चों ने नियमित सरकारी स्कूलों में दाखिला ले लिया है।

शहरी और ग्रामीण अनुपात में बड़ा अंतर

भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में 19 से 20 छात्रों पर 1 शिक्षक है। इसके विपरीत, पिछड़े व आदिवासी इलाकों (जैसे सिंगरौली में 42, झाबुआ में 38 और छतरपुर-टीकमगढ़ में 35 छात्रों पर 1 शिक्षक) में स्थिति काफी चिंताजनक है, जबकि एनईपी के अनुसार यहां 25 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए।

5 जिलों में शिक्षकों का जमावड़ा

राज्य के कुल 3.08 लाख शिक्षकों में से 10.55त्न (32,612 शिक्षक) केवल 5 जिलों—ग्वालियर, उज्जैन, सतना, मंडला और रायसेन में पदस्थ हैं। देश में प्रति स्कूल औसतन 7 शिक्षक हैं, जबकि मध्य प्रदेश में यह औसत घटकर 6 रह जाता है। प्रदेश के 2,269 सरकारी स्कूल केवल 1 शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जहां 62,151 बच्चे नामांकित हैं। माध्यमिक स्तर (9वीं-10वीं) पर पढ़ा रहे 20.3त्न शिक्षकों के पास कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं है।

मुरैना के चक्कपुरा में जर्जर स्कूल भवन के कारण 50 बच्चों को 1 शिक्षक पेड़ के नीचे पढ़ाता है। बारिश होने पर स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। राजगढ़ के बड़ल्या में प्राथमिक स्कूल का भवन पिछले 5 सालों से जर्जर है। छत में छेद और शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण 9 बच्चे खेड़ापति हनुमान मंदिर के दलान में पढ़ाई करते हैं।

इंदौर, जबलपुर और भोपाल को मिलेगा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सराहना पुरस्कार

भोपाल। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026' में मध्यप्रदेश ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के ध्येय को साकार करते हुए देश में पुनः अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'स्वच्छ वायु, स्वस्थ भारत' के दूरदर्शी विजन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल एवं पर्यावरण-हितैषी नेतृत्व में प्रदेश ने प्रदूषण नियंत्रण, हरित आवरण विस्तार और नागरिक सहभागिता की दिशा में एक स्वर्णिम अध्याय रचा है। इस राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में प्रदेश के इंदौर एवं जबलपुर को शहर स्तरीय उत्कृष्ट वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए तथा भोपाल नगर निगम के वार्ड क्रमांक-60 को वार्ड स्तरीय नवाचारों के लिए 'स्वच्छ वायु सराहना पुरस्कार' से अलंकृत किया जाएगा। यह राष्ट्रीय सम्मान 7 सितम्बर 2026 को नई दिल्ली स्थित इंदिरा पर्यावरण भवन के गंगा ऑडिटोरियम में 'स्वच्छ वायु दिवस' समारोह के अवसर पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा प्रदान किया जाएगा। देशभर में स्वच्छता के सर्वोत्कृष्ट प्रतिमान के रूप में स्थापित इंदौर शहर ने स्वच्छ वायु प्रबंधन के क्षेत्र में भी अपनी तकनीकी दक्षता एवं दृढ़ इच्छाशक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। इंदौर नगर निगम द्वारा प्रभावी रूप से संचालित धूल नियंत्रण उपायों, वैज्ञानिक सड़क सफाई व्यवस्था, हरित पट्टियों के निरंतर विस्तार, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के सुव्यवस्थित प्रबंधन तथा सघन जन-अभियानों ने शहर की आबो-हवा को निर्मल बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई है।

जोहेरी मोल डोमिंगेज के सिर सजा मिस वर्ल्ड 2026 का ताज

मिस वर्ल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, जोहेरी एक टीजर, सोशल एक्टिविस्ट और कम्युनिकेटर हैं. उन्होंने यूनिवर्सिडाड इबेरोअमेरिकाना से बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है. जोहेरी 'वॉयसेज ऑफ टुमॉरो' की फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं. इस संस्था के जरिए वह कमजोर और जरूरतमंद समुदायों के बच्चों और युवाओं के लिए अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देती हैं.

कल यानी 5 सितंबर को वियतनाम में मिस वर्ल्ड का ग्रैंड फिनाले आयोजित हुआ. इस कॉम्पिटिशन में करीब 111 देशों ने हिस्सा लिया था. जिसमें भारत से निकिता पोरवाल प्रतिनिधित्व करने पहुंची थी. लेकिन टॉप 20 में जगह नहीं बना पाईं और पहले ही एलिमिनेट हो गईं. वहीं, सबकी निगाहें विनर पर टिकी हुई थीं, जिसका ऐलान भी हो गया है. मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोल डोमिंगेज ने अपने नाम कर लिया है.उन्होंने स्पेन की एलिजाबेथ रेयनेस को पीछे छोड़ते हुए यह ताज जीता, जो फर्स्ट रनर-अप रहीं. वहीं मलेशिया की तानुसिया चेट्टी सेकेंड रनर-अप बनीं. जोहेरी को उनकी पिछली विजेता थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगस्री ने ताज पहनाया. ओपल ने पिछले साल आयोजित मिस वर्ल्ड के 72वें संस्करण में जीत हासिल की थी और वह अपने देश की पहली कंटेस्टेंट थीं, जिन्होंने यह खिताब जीता था.मिस वर्ल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, जोहेरी एक टीजर, सोशल एक्टिविस्ट और कम्युनिकेटर हैं. उन्होंने यूनिवर्सिडाड इबेरोअमेरिकाना से बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है. जोहेरी 'वॉयसेज ऑफ टुमॉरो' की फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं. इस संस्था के जरिए वह कमजोर और जरूरतमंद समुदायों के बच्चों और युवाओं के लिए अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देती हैं. वह अंग्रेजी में साहित्य और सोशल स्टडीज भी पढ़ाती हैं और बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के साथ बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं. इसके अलावा जोहेरी ni ision ew ok' entana a is é में बतौर संवाददाता भी काम करती हैं. इस शो के जरिए वह डोमिनिकन संस्कृति, सामाजिक मुद्दों और कम्युनिटी से जुड़ी कहानियों को सामने लाती हैं. वह o a i esकी एंबेसडर और प्रोफेशनल मॉडल भी हैं.

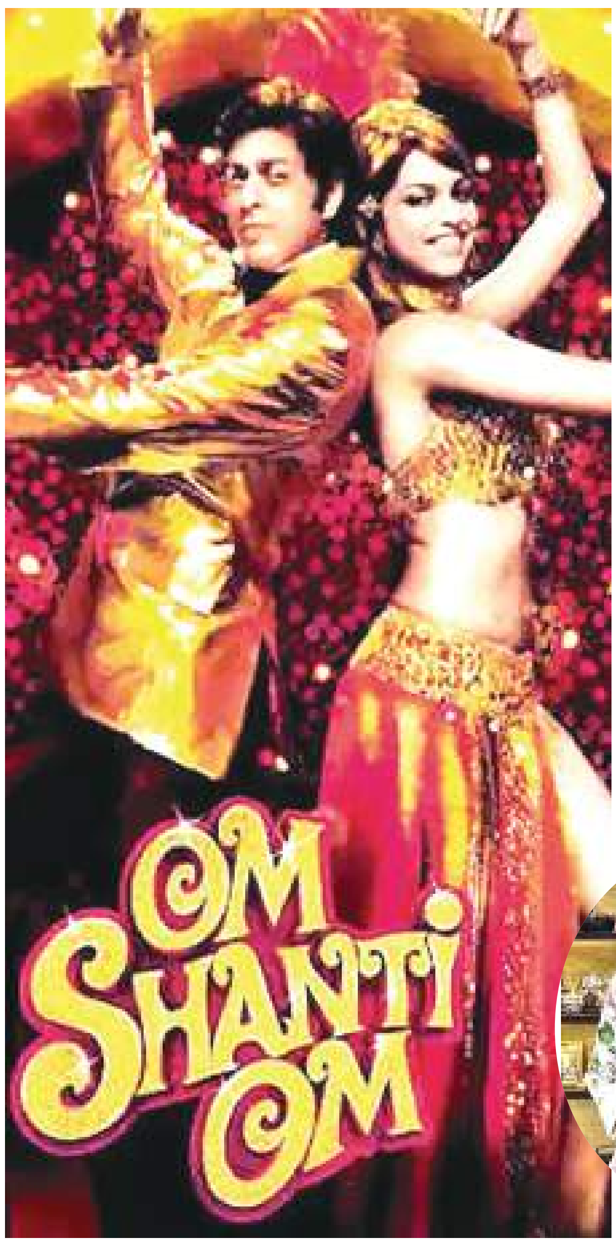

90s के रेट्रो अंदाज में नोरा का ग्लैमरस लुक, नए अंदाज में दिखा पुराना जलवा

नोरा फतेही अपने फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। नोरा ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह 90ह्य के फैशन से इंस्पायर्ड लुक में नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि उन्होंने पुराने दौर के फैशन को बिल्कुल उसी तरह नहीं अपनाया, बल्कि उसमें अपना मॉडर्न अंदाज भी जोड़ा है। नोरा का यह लुक देखने में ग्लैमरस होने के साथ काफी स्टाइलिश भी लग रहा है। यही वजह है कि उनकी तस्वीरों पर लोगों का ध्यान जा रहा है।नोरा ने इस लुक में सफेद रंग की फिटेड क्रॉप शर्ट पहनी है। शर्ट की डिजाइन काफी अलग है और इसे कमर के पास बांधा गया है। इसकी वजह से पूरे लुक में 90ह्य वाला फैशन साफ नजर आता है।सफेद शर्ट को उन्होंने इस तरह पहना है कि यह लुक को ज्यादा भारी नहीं बनाती। इसके साथ उनका मेकअप और हेयरस्टाइल भी काफी अच्छी तरह मैच कर रहा है।इस लुक में डेनिम भी खास हिस्सा है। नोरा ने नीले रंग की डेनिम स्कर्ट को सफेद शर्ट के साथ जोड़ा है। स्कर्ट पर सामने की तरफ बड़े बटन दिए गए हैं, जो पूरे पहनावे को थोड़ा और रेट्रो लुक दे रहे हैं।90ह्य के फैशन में डेनिम का काफी इस्तेमाल होता था। नोरा ने इसी पुराने फैशन को अपने अंदाज में पेश किया है। उनका यह लुक उन लोगों को भी पसंद आ सकता है, जिन्हें पुराने दौर का फैशन आज के स्टाइल के साथ पहनना पसंद है।नोरा ने इस लुक के साथ गोल्डन नेकलेस और बड़े गोल ईयररिंग्स पहने हैं। ज्वेलरी उनके पूरे पहनावे में ग्लैमर जोड़ रही है। खास बात यह है कि उन्होंने बहुत ज्यादा गहने नहीं पहने, फिर भी लुक काफी आकर्षक नजर आ रहा है। बालों को उन्होंने ऊपर की तरफ बांधा है और कुछ लटें चेहरे के पास खुली रखी हैं। इससे उनका लुक थोड़ा आराम वाला और 90ह्य फिल्मों की हीरोइनों जैसा महसूस होता है।

ओम शांति ओम के लिए बनाया गया था मसकली गाना! फराह खान ने किया बड़ा खुलासा

साल 2007 में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म ओम शांति ओम बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है. फिल्म के गाने आज भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें दिल्ली 6 फिल्म का एक पॉपुलर गाना होने वाला था. जी हां, इसका खुलासा खुद फिल्म की डायरेक्टर फराह खान ने किया है.फराह खान ने अपने लेटेस्ट यूट्यूब चैनल के लेटेस्ट एपिसोड में इस बार म्यूजिक कंपोजर और सिंगर विशाल ददलानी के फार्म हाउस पर उनसे मुलाकात की. जहां उन्होंने अपने पुराने रिश्ते के बारे में बातचीत की. फराह ने बताया कि वो ओम शांति ओम के लिए सबसे पहले दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर एआर रहमान के पास गईं थीं और उन्होंने फिल्म के लिए मसकली गाना बनाया था. लेकिन बाद में फिल्म के म्यूजिक को विशाल ददलानी और शेखर रवजियानी की जोड़ी ने संभाला. एआर रहमान ने फिल्म के लिए मसकली गाना बनाया था जो बाद में म्यूजिक डायरेक्टर बदलने की वजह से उस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सका था.फराह ने कहा- रहमान ने ओम शांति ओम के लिए जो पहला गाना बनाया था, वो था मसकली! मुझे नहीं पता मैं इसे कहां रखती, लेकिन मुझे वह गाना और वह शब्द दोनों बहुत पसंद हैं।

अनन्या पांडे का 3डी ड्रेस लुक वायरल धागों से सजी ड्रेस ने बढ़ाया ग्लैमर

अनन्या पान्डे के जब भी लुक्स की बात आती है तो वे अपने लुक्स को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहती है क्योंकि उनकी ड्रेस हो या एक्सेसरीज सभी बेहद डिफरेंट होती है जो उन्हे औरो से अलग बना देती है। और अब जब मुंबई में आयोजित ब्रांड के एक इवेंट में अनन्या पांडे ने राहुल मिश्रा की लोर-ग्रेजिंग कॉलम ड्रेस पहनी। ड्रेस में डीप प्लंजिंग नेकलाइन थी, जिसे उन्होंने पियाजेट की शानदार घड़ी के साथ पेयर किया। उनका लुक बेहद शानदार और रॉयल नजर आ रहा था। आजकल फैशन की दुनिया में अनन्या पांडे की लगातार अपनी पहचान मजबूत कर रही हैं और उनकी इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है। एक्ट्रेस पहले ही शैनल की पहली ग्लोबल एंबेसडर बन चुकी हैं। इसी साल जून में स्विट्जरलैंड की लग्जरी वॉच ब्रांड पियाजेट ने भी उन्हें अपने ब्रांड का 'फ्रेंड ऑफ द मैसन' नियुक्त किया था। साथ ही मुंबई के हाल फिलहाल इंवेट में भी उन्होंने लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर ही दिया। उनकी ड्रेस से लेकर वॉच सभी में बेहद रॉयल और अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। बॉडी-हगिंग फिट वाली इस ड्रेस की खासियत इसकी स्ट्रक्चर्ड प्लंजिंग नेकलाइन और थ्री-डायमेंशनल इफेक्ट है। यह ड्रेस पहली बार राहुल मिश्रा के फॉल 2026 हाउट कॉउचर कलेक्शन देवी में पेरिस में पेश की गई थी।ड्रेस को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह देखने में पत्थर पर की गई नक्काशी जैसी लगे। इसे ट्रॉम्प-ल-ऑयल तकनीक कहा जाता है। यह एक फ्रेंच आर्टिस्टिक तकनीक है, जिसमें सपाट सतह पर तीन आयामी डिजाइन का भ्रम पैदा किया जाता है।खास बात यह है कि इस प्रभाव को बनाने के लिए केवल धागों की कढ़ाई का इस्तेमाल किया गया है। अलग-अलग रंगों के धागों से बने फ्रेंच नॉट्स ने ड्रेस की पूरी दिखाई देने वाली सतह को कवर किया है। वहीं, बारीक रेशम के धागों और लगातार की गई सिंपल स्टिचिंग के जरिए उभरी हुई सतह तैयार की गई है। इससे ड्रेस में शानदार चियारोस्क्यूरो इफेक्ट दिखाई देता है, यानी रोशनी और छाया का गहरा कंट्रास्ट।अनन्या के लुक का सबसे खास हिस्सा थी पियाजेट लाइमलाइट गाला वॉच। 18 कैरेट की इस घड़ी में 32 एम एम का डायल है, जिसे इंद्रधनुष के रंगों से प्रेरित कीमती रत्नों से सजाया गया है। इसमें लग्जरी हाउस की सिग्नेचर प्लेस डेकारेशन स्टाइल भी देखने को मिलती है। इस घड़ी को स्विस वॉचमेकर जीन-क्लाउड ग्युइट ने 1973 में डिजाइन किया था। अपनी आकर्षक और सेंसुअल डिजाइन के कारण यह घड़ी आज भी लग्जरी वॉच की दुनिया में खास पहचान रखती है और यूरोप समेत दुनियाभर के हाई-सोसाइटी फैशन में पसंद की जाती रही है।

अल्काराज और मेदवेदेव US ओपन के चौथे राउंड में पहुंचे

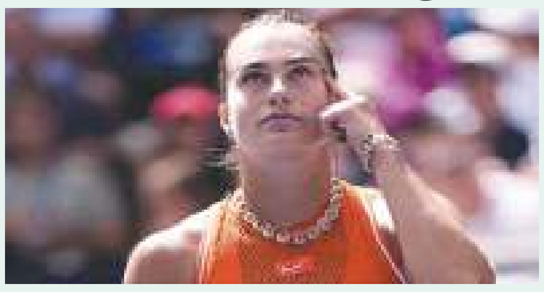

सबालेंका के मैच में गांजे की बदबू से रुका खेल, विंबलडन फाइनलिस्ट मुचोवा बाहर

न्यूयार्क (एजेंसी)। न्यूयॉर्क में शुक्रवार को यूएस ओपन 2026 के तीसरे राउंड में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने चीन के वू यिबिंग को 6-3, 6-4, 6-1 से हराकर मेंस सिंगल्स के चौथे राउंड में पहुंच गए। 139 दिन बाद सिंगल्स कोर्ट पर लौटे अल्काराज ने 2 घंटे 20 मिनट में मैच जीता। वहीं, डेनियल मेदवेदेव ने आर्थर रिंडरकनेच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर अंतिम-16 में जगह बनाई। विमेंस सिंगल्स में

डिफेंडिंग चैंपियन आर्यना सबालेंका ने मैच के दौरान स्टैंड्स से आ रही गांजे की बदबू की शिकायत की, जबकि एम्मा नवारो ने विंबलडन फाइनलिस्ट करोलिना मुचोवा को हराकर बड़ा उलटफेर किया। विमेंस सिंगल्स में दुनिया की नंबर-1 खिलाड़ी और डिफेंडिंग चैंपियन आर्यना सबालेंका के तीसरे राउंड के मुकाबले में अजीब स्थिति बन गई।

चोट से वापसी के बाद लय में लौट रहे अल्काराज

कलाई की चोट के कारण अप्रैल से सिंगल्स कोर्ट से दूर रहे अल्काराज टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। सात बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन अल्काराज ने पहले राउंड में सीधे सेटों में जीत हासिल की थी, जबकि दूसरे राउंड में पुर्तगाल के जेमी फारिया के खिलाफ एक सेट गंवाना पड़ा था।

वहीं तीसरे राउंड में वू यिबिंग के खिलाफ अल्काराज ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाए रखी। जीत के बाद अल्काराज ने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो मैं जितना सोच रहा था, उससे बेहतर स्थिति में हूं। पहले मैच के बाद मुझे लगा था कि शारीरिक रूप से परेशानी होगी, लेकिन मेरी रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है।'

मेदवेदेव ने भी सीधे सेटों में जीत दर्ज की 2021 के यूएस ओपन चैंपियन डेनियल मेदवेदेव ने तीसरे राउंड में फ्रांस के आर्थर रिंडरकनेच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। मेदवेदेव ने टूर्नामेंट में अब तक अपने तीनों मुकाबले सीधे सेटों में जीते हैं। अगले राउंड में उनका सामना अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो या मोनाको के वालेंटिन वाचेरोत से होगा।

नवारो ने विम्बलडन फाइनलिस्ट मुचोवा को हराया

विमेंस सिंगल्स में अमेरिका की एम्मा नवारो ने बड़ा उलटफेर करते हुए करोलिना मुचोवा को 6-3, 7-5 से हराकर चौथे राउंड में जगह बनाई।मुचोवा इस साल विम्बलडन की रनर-अप रही थीं और स्ओपन की दो बार सेमीफाइनलिस्ट भी हैं। वह टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टॉप-10 खिलाड़ी बनीं।नवारो की यह इस सीजन में किसी टॉप-10 खिलाड़ी के खिलाफ तीसरी जीत है। वह 2024 यूएस ओपन के सेमीफाइनल में भी पहुंच चुकी हैं।चौथे राउंड में नवारो का सामना एलीना स्वितोलिना या एना कलिन्स्काया से होगा।

सात्विक-चिराग चीन मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंचे

डेनमार्क की जोड़ी को हराया, पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 श्रीकांत क्वार्टर फाइनल में हारे

शेनझेन (एजेंसी)। भारत के सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीन मास्टर्स 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली।

इस जोड़ी ने शुक्रवार को डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। चीन के शेनझेन शहर में खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में भारतीय जोड़ी ने 15-17 से पिछड़ने के बाद वापसी की। उन्होंने तीसरे गेम के आखिरी सात में से छह पॉइंट जीतकर मैच अपने नाम किया।

सात्विक-चिराग ने दबाव में वापसी की- भारतीय जोड़ी ने पहले गेम में तेज शुरुआत की और 15-5 की बढ़त बना ली। उन्होंने इस गेम को 21-13 से जीतकर मैच में 1-0 की बढ़त बनाई। दूसरे गेम में डेनमार्क की जोड़ी ने जोरदार वापसी की। गेम में स्कोर बराबरी का चल रहा था, लेकिन एस्ट्रुप और रासमुसेन ने आखिरी आठ में से सात पॉइंट जीत लिए। तीसरे गेम में भी डेनमार्क की जोड़ी 17-15 से आगे थी। रैलियों में उसका दबदबा था। सात्विक और चिराग ने आखिरी सात में से छह पॉइंट जीतकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया।

श्रीकांत सीधे गेम में हारे, ली यू ने हराया

पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 किदांबी श्रीकांत का अभियान क्वार्टर फाइनल में हार के साथ खत्म हो गया। उन्हें हांगकांग के ली चेक यू ने 21-16, 21-16 से हराया। श्रीकांत ने दोनों गेम में कुछ मौकों पर लय बनाई, लेकिन वह अपनी चुनौती को कायम नहीं रख सके। ली चेक यू ने संयम बनाए रखा और सीधे गेम में मुकाबला जीत लिया। वर्ल्ड नंबर 13 लक्ष्य को कनाडा के वर्ल्ड नंबर 9 विक्टर लाई ने 38 मिनट चले मुकाबले में 21-14, 21-7 से हराया।

भारतीय अंडर 19 टीम के लेग स्पिनर रोहित यादव पर 2 साल का बैन

उम्र में गड़बड़ी के कारण कार्रवाई

नई दिल्ली । क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (सीएबी) को रोहित यादव के जन्म से जुड़े कागजात में उम्र को लेकर बड़ी गड़बड़ी मिली है, जिसके बाद भारत की अंडर-19 पुरुष टीम के लेग-स्पिनर पर दो साल का बैन लगा दिया गया है। यादव जुलाई में श्रीलंका दौरे पर गई भारत की अंडर-19 पुरुष टीम का हिस्सा थे और उन्होंने यूथ टेस्ट में 6 विकेट भी लिए थे। हालांकि, कागजात की जांच में जन्म-रिकॉर्ड में बड़ी गड़बड़ी पाए जाने के बाद अब उन्हें खेल के सभी फॉर्मेट में खेलने से रोक दिया गया है। इस कारण उन्हें उस टीम से भी बाहर कर दिया गया है, जो इस महीने के आखिर में राजकोट और अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ पांच वनडे और दो मल्टी-डे मैच खेलने वाली है। शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने 'आईएएनएस' को बताया, 'हां, सीएबी से जानकारी मिलने के बाद उन्हें टीमों से हटा दिया गया है। दोनों टीमों में उनकी जगह कौन लेगा, इस बारे में बाद में पता चलेगा।' सीएबी की जांच में यादव से जुड़े कई दस्तावेजों में अलग-अलग जानकारी मिली। जांच के दौरान उनके तीन अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र सामने आए, जिनमें जन्म वर्ष 2006, 2007 और 2009 दर्ज है। इसके अलावा, 2014 से 2021 के बीच उनके आधार कार्ड की जानकारी में भी कई बार बदलाव किए गए थे। माना जा रहा है कि इन अलग-अलग रिकॉर्ड की वजह से उनकी उम्र को लेकर करीब 27 महीने का अंतर सामने आया है।

सीएबी की कार्रवाई के तहत, उम्र में गड़बड़ी और कागजात में अनियमितताओं के कारण कुल 65 खिलाड़ियों को 2026-27 और 2027-28 घरेलू सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर से रोक दिया गया है। सजा पाने वालों में भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रवि कुमार भी शामिल हैं। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अंडर-19 विश्व कप 2022 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 34 रन देकर 4 विकेट लिए थे और भारत को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी।

भारत जूनियर मेंस हॉकी एशिया कप में 14-0 से जीता

इंडोनेशिया को हराया, प्रभदीप ने 5 और अनमोल ने 4 गोल किए

नईदिल्ली (एजेंसी)। भारत की जूनियर मेंस हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप 2026 की शुरुआत 14-0 की बड़ी जीत से की। ग्रुप ए के पहले मुकाबले में भारत ने इंडोनेशिया को हराया। प्रभदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 5 गोल किए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कप्तान अनमोल एक्का ने 4, अजीत यादव ने 3, जबकि हरपाल और आशु मौर्य ने 1-1 गोल किया।

हाफ-टाइम तक स्कोर 6-0- दूसरे क्वार्टर में कप्तान अनमोल ने 16वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल किया। इसके चार मिनट बाद अजीत यादव ने गोल कर भारत की बढ़त 4-0 कर दी।

पहले क्वार्टर में भारत की बढ़त

भारत ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और इंडोनेशिया पर लगातार दबाव बनाए रखा। प्रभदीप ने 5वें मिनट में गोल कर भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद हरपाल ने 8वें मिनट में गोल करके स्कोर 2-0 कर दिया। इंडोनेशिया भारतीय टीम के तेज हमलों और लगातार मूवमेंट का सामना नहीं कर सका।

एशियाड में आईओए अलग होटल की व्यवस्था नहीं करेगा

बीसीसीआई अपनी पसंद का होटल ले सकता है, लेकिन तब पूरी जिम्मेदारी बोर्ड की होगी

नईदिल्ली (एजेंसी)। जापान में होने वाले एशियन गेम्स के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भारतीय ओलिंपिक संघ (आईओए) अलग से होटल की व्यवस्था नहीं करेगा। अगर बीसीसीआई आयोजकों की ओर से तय होटलों के बजाय अपनी पसंद का होटल चुनता है, तो खिलाड़ियों के ठहरने, खाने, स्थानीय परिवहन और मैच वेन्यू तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बोर्ड की होगी। आईओए के सीईओ रघुराम अय्यर ने कहा कि एशियन गेम्स में शामिल सभी 36 खेलों के खिलाड़ियों, कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ समान व्यवहार किया जाएगा।भारत ने 2023 एशियन गेम्स में मेंस और विमेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था।

बीसीसीआई भेजेगा एडवांस टीम

बीसीसीआई सीईओ हेमांग अमीन और आईओए सीईओ रघुराम अय्यर के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई है।बीसीसीआई अगले हफ्ते की शुरुआत में एक एडवांस टीम जापान भेजेगा।यह टीम होटल, क्रिकेट वेन्यू और दूसरी स्थानीय सुविधाओं का जायजा लेगी।इसके बाद बोर्ड तय करेगा कि आयोजकों की ओर से दिए गए होटलों में रहना है या अपनी व्यवस्था करनी है।

मेंस टीम को 3-स्टार, विमेंस टीम को 4-स्टार होटल

एशियन गेम्स के आयोजकों ने भारतीय मेंस टीम के लिए 3-स्टार एपीए होटल नागोया एकिमाए और विमेंस टीम के लिए 4-स्टार ग्रैंड होटल की व्यवस्था की है।दोनों होटलों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेटरों के आमतौर पर रहने वाले 5-स्टार होटल की तुलना में ये एक लेवल नीचे हैं। खिलाड़ियों के लिए कमरे ट्विन-शेयरिंग के आधार पर दिए जाएंगे। यही व्यवस्था बीसीसीआई के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

अलग होटल में भी लागू रहेंगे सुरक्षा और डोपिंग नियम

अगर बीसीसीआई अपनी व्यवस्था करता है तो क्रिकेटर एशियन गेम्स सिस्टम से बाहर नहीं होंगे। खिलाड़ियों पर गेम्स के सुरक्षा, एक्रेडिटेशन और एक्सेस प्रोटोकॉल लागू रहेंगे। बिना वैध एक्रेडिटेशन वाले बाहरी लोगों को खिलाड़ियों के होटल में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा वाडा और इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डोप-कंट्रोल अधिकारियों को खिलाड़ियों के ठिकाने की जानकारी देनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर रैंडम डोप टेस्ट किया जा सके।

महिला टीम पहले पहुंचेगी

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम दुबई में एशिया कप खेलने के बाद 13 सितंबर को भारत लौटेगी और 14 सितंबर को नागोया के लिए रवाना होगी।महिला टीम एशियन गेम्स में सीधे क्वार्टर फाइनल से अभियान शुरू करेगी। उसका पहला मुकाबला 18 सितंबर को होगा और टीम का टूर्नामेंट 22 सितंबर तक चलेगा।

'रनों और टनों से भरे साल की शुभकामनाएं'

युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को जन्मदिन की बधाई दी

नई दिल्ली । पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने शुक्रवार को अपने अभिषेक शर्मा को उनके 26वें जन्मदिन पर खास शुभकामनाएं दीं। अभिषेक शर्मा को एक विस्फोटक बल्लेबाज बनाने में युवराज सिंह का मार्गदर्शक के रूप में अहम योगदान रहा है। युवराज ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करते हुए अभिषेक को जन्मदिन की बधाई दी। युवराज ने लिखा, 'सर अभिषेक, यह आपका जन्मदिन है। कितना शुभ दिन है। आप जैसे बन गए हैं, उससे प्यार करें - अपने आस-पास के लोगों के साथ शेयरिंग और केयरिंग, और एक लीडर। हमेशा अपनी नाकामियों से सीखते हैं और हर बार और ज्यादा मेहनत करने को तैयार रहते हैं। आपको रनों और टनों से भरे साल की शुभकामनाएं। हमेशा ढेर सारा प्यार।' वीडियो में युवराज और अभिषेक से रैश शॉट न खेलने के लिए कहते और उसकी गलतियों के लिए उससे सिट-अप करवाते हुए देखे जा सकते हैं। युवराज को यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'बोल मैं पहली बॉल ते लप्पा नहीं मारूंगा। अभिषेक सिट-अप्स में कान पकड़ते हैं और कहते हैं कि मैं पहली बॉल ते लप्पा नहीं मारूंगा। ' वीडियो में दोनों के बीच करीबी रिश्ते को भी दिखाया गया है, जिसमें युवराज के कुछ हल्के-फुल्के मजाक भी हैं। इसमें युवराज, अभिषेक और संजू सैमसन को स्टैंड से विंबलडन इवेंट में शामिल होते हुए भी दिखाया गया है।

बेन शेल्टन ने शापोवालोव को और टियाफो ने वचेरोट को हराकर

चौथे राउंड में जगह बनाई

न्यूयॉर्क । बेन शेल्टन ने डेनिस शापोवालोव को 3 घंटे 22 मिनट तक चले मुकाबले में हराकर यूएस ओपन 2026 के पुरुष एकल के चौथे राउंड में जगह बना ली है। शेल्टन ने शापोवालोव को 7-6(3), 6-7(5), 6-2, 6-4 से हराया।23 साल के अमेरिकी खिलाड़ी दूसरे सेट में दो बार सर्व नहीं कर पाए, जिससे शापोवालोव को वापसी करने का मौका मिला और फिर टाईब्रेक जीतकर मैच बराबर कर दिया। इस हार से शेल्टन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। उन्होंने तीसरे सेट में और ज्यादा आक्रामक तरीके से वापसी की और कनाडाई खिलाड़ी का स्तर गिरते ही फायदा उठाया। एक तेज रिटर्न विनर ने लाइन को पार करते हुए शेल्टन को चौथे राउंड की शुरुआत में ही ब्रेक करने में मदद की, और उन्होंने मुकाबला खत्म करने तक अपनी बढ़त बनाए रखी। इस जीत ने लेक्सस एटीपी हेड टू हेड राइवलरी में शापोवालोव पर शेल्टन के दबदबे को 5-0 कर दिया। उन्हें चौथे राउंड में स्टेफानोस सिटसिपास के साथ मुकाबला मिला है।

पूर्व वर्ल्ड नंबर 3 ने 18वीं सीड जिरी लेहेका को 2-6, 6-1, 7-6(3), 6-1 से हराकर अपनी वापसी की। दो बार के ग्रैंड स्लैम फाइनलिस्ट सिटसिपास ने पहले 10वीं सीड आर्थर फिल्स को हराया था और अब वह टूर्नामेंट में नौ बार खेलने के बाद पहली बार यूएस ओपन के चौथे राउंड में पहुंचे हैं।

टियाफो ने लुइस आर्मस्ट्रांग स्टेडियम में लाइट्स के नीचे 1 घंटे 59 मिनट में वैलेंटिन वचेरोट को 6-4, 6-2, 6-4 से हराया। 11वें सीड खिलाड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सिर्फ 13 अनफोर्स्ड गलतियों के मुकाबले 30 विनर लगाए और अपने पहले सर्व पॉइंट्स का 85 प्रतिशत जीता। इस नतीजे के साथ वह यूएस ओपन के चौथे राउंड में छठी बार पहुंचे। सीजन की यह उनकी 40वीं टूर-लेवल जीत थी। टियाफो अब अलेक्जेंडर ज्वेरेव और जैनिक सिनर के साथ 2026 में कम से कम 40 टूर-लेवल जीत वाले अकेले खिलाड़ी बन गए हैं। टियाफो का अगले दौर में सामना मेदवेदेव से होगा। मेदवेदेव आर्थर रिंडरकनेच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर चौथे राउंड में पहुंचे हैं।

सीपीएल 2026: दासुन शनाका का ऐतिहासिक शतक

सेंट किट्स ने सेंट लूसिया को 137 रन से हराया

वार्नर पार्क । कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2026 के 25वें मैच में श्रीलंकाई बल्लेबाज दासुन शनाका ने इतिहास रच दिया। सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की तरफ से खेलते हुए शनाका ने लीग के इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया। शनाका की शतकीय पारी की बदौलत सेंट किट्स ने सेंट लूसिया किंग्स को 137 रन के विशाल अंतर से हराया। सेंट लूसिया किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी सेंट किट्स की तरफ से पारी की शुरुआत जॉनसन चार्ल्स और काइल मायर्स ने की। शुरुआत अच्छी नहीं रही और मायर्स मात्र 1 रन बनाकर 8 के स्कोर पर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। चार्ल्स और फ्लेचर ने दूसरे विकेट के लिए 48 गेंदों पर 81 रन की साझेदारी की। चार्ल्स 23 गेंदों पर 26 रन बनाकर दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए। इसके बाद दासुन शनाका चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए।

श्री चरणी ने दीप्ति शर्मा को पीछे छोड़ा

खतरे में पूनम यादव का रिकॉर्ड

नई दिल्ली । भारतीय महिला क्रिकेट टीम दुबई में खेले जा रहे एशिया कप में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। लगातार 2 मैच जीतकर भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ एक और मैच खेलना है। गुरुवार को भारतीय टीम ने हांगकांग को 137 रनों से हराया। इस मैच में स्मृति मंधाना के विस्फोटक शतक के साथ ही श्री चरणी ने भी अपनी गेंदबाजी के खास उपलब्धि हासिल की। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए थे। हांगकांग 16.2 ओवर में 56 रन पर सिमट गई और 137 रन से हार गई। हांगकांग को 56 पर समेटने में श्री चरणी का अहम योगदान रहा। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने 3.2 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट लिए। इसके अलावा, दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए, जबकि नंदिनी शर्मा और प्रेमा रावत को भी 2-2 विकेट लिए। श्री चरणी ने 2 विकेट लेकर एक साल में सर्वाधिक टी20 विकेट लेने के वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में दीप्ति शर्मा को पीछे छोड़ दिया। चरणी ने 2026 में अब तक 31 टी20 विकेट लिए है। दीप्ति शर्मा ने 2024 में 30 और 2022 में 29 विकेट लिए थे। एक साल में सर्वाधिक टी20 विकेट लेने का महिला भारतीय रिकॉर्ड पूनम यादव के नाम है। पूनम ने 2018 में 35 विकेट लिए थे। श्री चरणी के पास इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने का भरपूर अवसर है। पूरी संभावना है कि जारी एशिया कप में ही चरणी एक साल में सर्वाधिक टी20 विकेट लेने वाली भारतीय महिला गेंदबाज होने का भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगी।

सार समाचार

तामोट प्लास्टिक पार्क में 84 प्रतिशत भूखंड खाली

भोपाल । सरकार ने तामोट में प्लास्टिक उद्योग का बड़ा हब खड़ा करने के लिए सडक, बिजली, पानी और दूसरी जरूरी सुविधाओं पर करीब 108 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, लेकिन इसके बावजूद पार्क अपेक्षित औद्योगिक गतिविधि नहीं पकड़ सका। मंडीदीप से करीब 15 किलोमीटर दूर विकसित देश के दूसरे सबसे बड़े प्लास्टिक पार्क में एक दशक के बाद भी अधिकांश भूखंड खाली हैं ।121.90 एकड़ में विकसित इस पार्क में 172 भूखंड आरक्षित किए गए हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 28 भूखंडों की बुकिंग हुई है। इनमें भी केवल 10 इकाइयां स्थापित हो पाई हैं। इन इकाइयों में करीब 10 से 15 करोड़ रुपये का निवेश और लगभग 150 लोगों को रोजगार मिलने की जानकारी है। यानी जिस पार्क से करीब 5 हजार प्रत्यक्ष और 15 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार की उम्मीद की गई थी, वहां रोजगार और निवेश दोनों लक्ष्य से काफी दूर हैं ।जमीन और सुविधाएं तैयार, उद्योगों का इंतजारतामोट प्लास्टिक पार्क की योजना करीब 12 साल पहले छोटे-बड़े प्लास्टिक उद्योगों को एक ही स्थान पर जमीन और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सहयोग से विकसित इस पार्क में अधोसंरचना खड़ी करने पर करीब 108 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

फूल माली समाज की प्रतिभाओं का सम्मान

भोपाल। हिन्दी भवन में फूल माली समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह-2026 आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महापौर श्रीमती मालती राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली फूल माली समाज की प्रतिभाओं को मेडल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया ।इस अवसर पर आयोजक संस्था श्री फूल माली समाज मंदिर ट्रस्ट भोपाल की ओर से महापौर श्रीमती मालती राय का भी सम्मान किया गया। समारोह में समाज की प्रतिभाओं की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें आगे भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया गया ।कार्यक्रम में पार्षद श्रीमती गीता माली सहित श्री फूल माली समाज मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी, आयोजक एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

एम्स भोपाल में डीएमडी जागरूकता कार्यक्रम आज

भोपाल। एम्स भोपाल में 7 सितंबर 2026 को ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (ऊटऊ) पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ह्यपहुंच बदले जिंदगीह्न (अॢ२२ उँल्लॅं२ छ्र५ी२) थीम पर होने वाले कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन, चिकित्सकों, मरीजों और उनके परिजनों को इस दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी के प्रति जागरूक करना है। डीएमडी में बच्चों की मांसपेशियां धीरे-धीरे कमजोर होती जाती हैं ।कार्यक्रम का आयोजन मेडिकल जेनेटिक्स विभाग द्वारा रेयर डिजीज उत्कृष्टता केंद्र और डॉक्टर्स फॉर यू के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, ट्रांसलेशनल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी तथा फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन विभाग शामिल होंगे ।मुख्य अतिथि कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) नरेन्द्र कोतवाल (रि.) होंगे। डीन एकेडेमिक्स प्रो. (डॉ.) रजनीश जोशी और मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रो. (डॉ.) विकास गुप्ता भी उपस्थित रहेंगे ।कार्यक्रम में डीएमडी की प्रारंभिक जांच एवं प्रबंधन, पुनर्वास तथा हृदय संबंधी जांच की भूमिका पर विशेषज्ञ व्याख्यान होंगे। आयोजकों के अनुसार बीमारी की समय पर पहचान और उचित प्रबंधन से मरीजों की जीवन गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाया जा सकता है।

हेर-टू पॉजिटिव मेटास्टेटिक स्तन कैंसर के आधुनिक उपचार पर विशेषज्ञ चर्चा

भोपाल। एम्स भोपाल के चिकित्सा कैंसर विज्ञान एवं रक्त रोग विभाग की संकाय सदस्य डॉ. आकांक्षा चौधरी ने चौथे ह्यभोपाल ऑन्कोलॉजी अपडेट्स 2026ह्न में विशेषज्ञ पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया। भोपाल में आयोजित सम्मेलन में हेर-टू पॉजिटिव मेटास्टेटिक स्तन कैंसर के आधुनिक उपचार और नई लक्षित दवाओं पर विशेषज्ञों ने चर्चा की ।डॉ. आकांक्षा चौधरी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में हेर-टू पॉजिटिव स्तन कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ट्रास्टुजुमैब डेरक्सटेकैन, पर्टुजुमैब और टुकाटिनिब जैसी लक्षित दवाओं के साथ कई आधुनिक उपचार विकल्प उपलब्ध हुए हैं। इनसे चरण-4 यानी शरीर के अन्य हिस्सों तक फैल चुके कैंसर में बीमारी को नियंत्रित करने और मरीजों की जीवन प्रत्याशा बेहतर करने की संभावनाएं बढ़ी हैं ।उन्होंने कहा कि अब कैंसर का उपचार केवल बीमारी के नाम के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि कैंसर की विशेषताओं और मरीज की स्थिति के अनुसार उपचार का चयन किया जाता है। इससे मरीजों को अधिक प्रभावी और व्यक्तिगत उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलती है ।सम्मेलन का आयोजन भोपाल कैंसर सेवा समिति के अंतर्गत नवोदय कैंसर अस्पताल द्वारा किया गया।

सड़कों से 17 पशु पकड़े, 5 घायल पशु आसरा भेजे

भोपाल। नगर निगम भोपाल द्वारा सड़कों, फुटपाथों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्वतंत्र विचरण करने वाले पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस भेजने की कार्रवाई लगातार जारी है। रविवार को निगम के गोवर्धन परियोजना शाखा के अमले ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 17 पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस भेजा। वहीं बीमार एवं घायल 5 पशुओं को उपचार के लिए आसरा पशु चिकित्सालय भेजा गया ।निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत नेहरू नगर डी-सेक्टर, बरखेड़ी खुर्द, जवाहर चौक, सुनेहरी बाग, शाहपुरा सी-सेक्टर, शंकर नगर, बरखेड़ा पठानी, भारती निकेतन और गोविंदपुरा सहित अन्य क्षेत्रों में कार्रवाई की गई है।

सीएम के फरमान, तीन बार निर्देश, फिर भी तारीख तय नहीं

मंत्रालय में नहीं लगी बायोमेट्रिक हाजिरी

भोपाल । सरकारी दफ्तरों में समय पर पहुंचने और जवाबदेही तय करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पिछले आठ महीने में तीन बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने के निर्देश दे चुके हैं, लेकिन व्यवस्था की शुरूआत उस मंत्रालय में ही नहीं हो पाई जहां से प्रदेश का प्रशासन चलता है। अप्रैल से नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही है, मशीनों और जरूरी सामग्री की खरीदी की प्रक्रिया भी शुरू हुई, लेकिन करीब पांच महीने गुजरने के बाद भी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू नहीं हो सकी। अब अधिकारियों का कहना है कि सिस्टम तैयार किया जा रहा है और करीब दो महीने में व्यवस्था शुरू हो सकती है। पहले चरण में मंत्रालय के साथ सतपुड़ा और विंध्याचल भवन को शामिल किया जाएगा ।मुख्यमंत्री ने पहली बार 7 जनवरी को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में सरकारी कार्यालयों का काम सुबह 10 बजे से शुरू करने और बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने को कहा था। उन्होंने यहां तक कहा था कि समय पर आने की आदत नहीं सुधरी तो सप्ताह में छह दिन काम की व्यवस्था फिर लागू करने पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद 15 मई को मुख्यमंत्री ने व्यवस्था की समीक्षा करते हुए प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने के निर्देश दिए।

उन्होंने इसे समयबद्धता और जवाबदेही बढ़ाने का जरिया बताया और खुद कार्यालयों में उपस्थिति का निरीक्षण करने की बात कही। फिर 25 अगस्त की समीक्षा बैठक में मंत्रालय, विंध्याचल और सतपुड़ा भवन के साथ सभी जिलों के सरकारी कार्यालयों में भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने की बात कही गई। इसके बावजूद मंत्रालय में अभी तक नई व्यवस्था जमीन पर नहीं उतर पाई है।

अप्रैल से तैयारी, पांच महीने बाद भी सिस्टम तैयार नहीं

मंत्रालय में अप्रैल से बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू करने की तैयारी थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने मशीनों और अन्य सामग्री की खरीदी के लिए एमपीएसआईडीसी को वर्क ऑर्डर जारी करने का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन खरीदी और सिस्टम तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ? के बावजूद व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। अधिकारियों के मुताबिक एमपीएसईडीसी सिस्टम तैयार कर रहा है और अब लगभग दो महीने में इसे शुरू किया जा सकता है। यानी जिस व्यवस्था को अप्रैल में शुरू करने की तैयारी थी, उसके लिए अब आगे भी करीब दो महीने का इंतजार करना पड़ सकता है।

पहले रजिस्टर, फिर फेस अटेंडेंस... दोनों बेअसर

मंत्रालय में कर्मचारियों की लेटलतीफी रोकने के लिए यह पहला प्रयोग नहीं है। इससे पहले भी दो व्यवस्थाएं लागू की जा चुकी हैं। जून 2024 में अटेंडेंस रजिस्टर में कर्मचारियों के हस्ताक्षर की व्यवस्था शुरू की गई थी। इसके बाद फरवरी 2025 में आधार बेस्ड फेस अटेंडेंस लागू की गई। लेकिन खबर के मुताबिक दोनों व्यवस्थाएं कर्मचारियों के समय पर कार्यालय पहुंचने की समस्या पर प्रभावी अंकुश नहीं लगा सकीं। अब तीसरी बार बायोमेट्रिक व्यवस्था से उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारी की उपस्थिति सीधे दर्ज होगी और हाजिरी में पारदर्शिता आएगी।

फाइव-डे वीक के बीच समय की पाबंदी बड़ा मुद्दा

प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में वर्ष 2021 से फाइव-डे वीक लागू है। 8 अप्रैल 2021 के आदेश के बाद कार्यालयों का समय सुबह 10 से शाम 6 बजे किया गया था। रविवार के साथ शनिवार को भी अवकाश रहने लगा।

ऐसे में सरकार की कोशिश है कि पांच दिन के कार्य सप्ताह में कार्यालयों का कामकाज तय समय के अनुसार हो और कर्मचारियों की उपस्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड रहे। लेकिन मंत्रालय में ही बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू होने में लगातार हो रही देरी ने सरकार की टाइमिंग और जवाबदेही वाली नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अब मंत्रालय से होगी व्यवस्था की परीक्षा

सरकार पहले मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर इसकी सफलता परखेगी। इसके बाद प्रदेश के अन्य सरकारी कार्यालयों में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मुख्यमंत्री तीन बार निर्देश दे चुके हैं, तो मंत्रालय में व्यवस्था लागू करने में पांच महीने से ज्यादा समय क्यों लग रहा है? सरकार जिस बायोमेट्रिक सिस्टम को पूरे प्रदेश में जवाबदेही बढ़ाने का जरिया बता रही है।

30 से अधिक साइटों पर पड़ा 12 लाख टन से पुराना कचरा

मप्र में कचरा हटाने की पहली डेडलाइन फेल, अब 2027 का नया टारगेट

भोपाल । मध्य प्रदेश के शहर भले ही स्वच्छता के मामले में देशभर में अपनी पहचान बना रहे हों, लेकिन वर्षों से जमा कचरे के पहाड़ अब भी नगरीय निकायों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। प्रदेश की 30 से अधिक डंपिंग साइटों पर 12 लाख टन से ज्यादा लीगेसी वेस्ट जमा होने की जानकारी सामने आई है। खास बात यह है कि इस पुराने कचरे के निपटान के लिए जून 2026 तक की डेडलाइन तय की गई थी, लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। अब सरकार ने वर्ष 2027 के अंत तक शत-प्रतिशत लीगेसी वेस्ट हटाने का नया लक्ष्य तय किया है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया गया है। सरकार का कहना है कि पुराने कचरे की मात्रा का थर्ड पार्टी सत्यापन कराया जा रहा है और डंपिंग साइटों के रेमेडिएशन का काम आगे बढ़ाया जा रहा है।

लीगेसी वेस्ट यानी वर्षों से लैंडफिल, खुले मैदानों या डंपिंग साइटों पर जमा पुराना कचरा हटाने के लिए जून 2026 तक का लक्ष्य निर्धारित था। नगरीय निकायों को अपने-अपने शहरों में पुराने कचरे की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश भी दिए गए थे।

इसके बावजूद प्रदेश की कई साइटों से कचरा पूरी तरह नहीं हटाया जा सका। अब विभाग ने निकायों को 2027 तक लंबित काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इससे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब पहली डेडलाइन पूरी नहीं हो सकी तो नई समयसीमा में काम पूरा कराने के लिए व्यवस्था में क्या बदलाव किए जाएंगे।

30 से ज्यादा साइटों पर कचरे का ढेर

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन 30 से अधिक डंपिंग साइटों की है, जहां वर्षों से कचरा जमा होता आ रहा है।

निजी कॉलेजों के छात्रों को सबसे ज्यादा झटका; 30 सितंबर तक आवेदन का मौका

एडमिशन में देरी ने बिगाड़ा छात्रवृत्ति का गणित

भोपाल । मध्य प्रदेश में कॉलेज विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन को लेकर राहत की खबर है। उच्च शिक्षा विभाग ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है। इससे उन विद्यार्थियों को आवेदन का अतिरिक्त अवसर मिल गया है, जिनका कॉलेज में प्रवेश हो चुका है, लेकिन समय पर छात्रवृत्ति का फार्म नहीं भर पाए थे ।दरअसल, प्रदेश के कॉलेजों में रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया अगस्त के अंतिम सप्ताह तक चली। इसके कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का प्रवेश देर से हुआ और वे तय समय सीमा में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सके। इसका सबसे ज्यादा असर निजी कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर पड़ा। कॉलेज प्रबंधनों की ओर से भी आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग उच्च शिक्षा विभाग के सामने रखी गई थी।

30 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन

अब विद्यार्थी 30 सितंबर तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए कॉलेज से प्रवेश संबंधी जानकारी अपडेट करवाने के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी

कई योजनाओं का मिलेगा लाभ

प्रदेश में विद्यार्थियों की सामाजिक श्रेणी और पात्रता के अनुसार कई छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित हैं। योजनाओं के अनुसार पात्रता, आय सीमा और जरूरी दस्तावेज अलग-अलग निर्धारित हैं।

बैंक खाते की जानकारी जरूरी

छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को आवेदन में बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है।

67 फास्ट ट्रैक कोर्ट, फिर भी 10,628 मामले लंबित

मप्र में दुष्कर्म-पॉक्सो केसों का बोझ

भोपाल । मध्यप्रदेश में दुष्कर्म और पॉक्सो मामलों के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था तो पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रही है, लेकिन लंबित मामलों का आंकड़ा सवाल खड़े कर रहा है। प्रदेश में 67 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्वीकृत और सभी 67 संचालित हैं। इसके बावजूद 31 मार्च 2026 तक इन अदालतों में 10,628 मामले लंबित थे। सबसे गंभीर स्थिति उन मामलों की है, जिनमें जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी सुनवाई और फैसला समय पर नहीं हो सका। लंबित मामलों में 9,278 प्रकरण ऐसे हैं, जिनमें चार्जशीट दाखिल हुए दो महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। अब सरकार कोर्टवार आंकड़े जुटाकर यह पता लगाने की तैयारी में है कि देरी

आखिर किस स्तर पर हो रही है-पुलिस जांच, डीएनए रिपोर्ट, अभियोजन, गवाहों की पेशी या अदालत की सुनवाई प्रक्रिया में।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के लिए निर्धारित मानक के अनुसार प्रत्येक कोर्ट को साल में 165 दुष्कर्म और पॉक्सो मामलों का निपटारा करना है। इसका औसत करीब 13.75 केस प्रतिमाह, यानी लगभग 14 केस प्रति माह है। लेकिन जनवरी से दिसंबर 2025 के दौरान मध्यप्रदेश में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का औसत निस्तारण केवल 6.11 मामले प्रति कोर्ट प्रति माह रहा। यानी लक्ष्य के मुकाबले वास्तविक निस्तारण करीब आधे से भी कम है। यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का मूल उद्देश्य ही ऐसे मामलों को सामान्य अदालतों की तुलना में तेजी से निपटाना है। यदि अदालतों की संख्या पर्याप्त होने के बावजूद निस्तारण की रफ्तार लक्ष्य तक नहीं पहुंच रही, तो अब केवल कोर्ट बढ़ाना समाधान नहीं होगा।

तीन महीने में 10,533 नए केस आए, निपटे सिर्फ 1,323

जनवरी से मार्च 2026 के बीच फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में 10,533 नए मामले आए। इसी अवधि में सिर्फ 1,323 मामलों का निस्तारण हुआ। और इससे भी चिंताजनक तथ्य यह है।

विंध्य नागरिक अधिकार मंच ने गांधी प्रतिमा के सामने दिया धरना

कल्पना मिश्रा केस की सीबीआई जांच कराने की मांग

भोपाल । कल्पना मिश्रा की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर विंध्य नागरिक अधिकार मंच ने रविवार को गांधी प्रतिमा के सामने एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। मंच के अध्यक्ष दिलीप तिवारी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में विंध्य क्षेत्र के नागरिकों और सामाजिक कार्यकताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कल्पना मिश्रा को न्याय दो- सीबीआई जांच लागू करो, स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करो जैसे नारे लगाए। मंच ने कहा कि कल्पना मिश्रा ने मौत से पहले इलाज और मदद के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनी गई। अब उसके साथ हुई घटना पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए न्याय का सवाल बन गई है ।मंच अध्यक्ष दिलीप तिवारी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही मामले की सीबीआई जांच नहीं कराई तो पूरा विंध्य भोपाल में एकजुट होकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा। साथ ही मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की जाएगी। धरने में अनीश शर्मा, भूपेन्द्र मिश्रा, अभिषेक तिवारी, प्रवीण शर्मा, सुरजन, संदीप विश्वकर्मा, देवराज राणा, अंकित रघुवंशी और धीरेंद्र राणा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

मजिस्ट्रियल जांच पर सवाल

मंच ने मामले में कराई जा रही मजिस्ट्रियल जांच पर भी सवाल उठाए। दिलीप तिवारी ने कहा कि जिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हीं के स्तर पर होने वाली जांच से निष्पक्षता को लेकर सवाल बने रहेंगे। इसलिए सरकार को मजिस्ट्रियल जांच के

बजाय केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच करानी चाहिए।

स्वास्थ्य विभाग में वसूली और मनमानी का आरोप

मंच ने रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। आरोप लगाया गया कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल रहा और कुछ डॉक्टर निजी नर्सिंग होम में सेवाएं देने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। मंच का आरोप है कि सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को निजी अस्पतालों में बुलाने और इलाज के नाम पर वसूली का खेल चल रहा है। मंच ने अस्पताल के अधीक्षक से जुड़े निजी अस्पताल के संचालन को लेकर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि दोहरे पदों से जुड़े लोगों तथा निजी चिकित्सा संस्थानों के संचालन की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मंच ने ऐसे मामलों में दोष सिद्ध होने पर सेवा समाप्त करने तक की कार्रवाई की मांग की।

12 और सडकों पर लगेगा टोल, सरकार का सालाना 3 हजार करोड़ कमाई का प्लान

एमपी में अब सडक सफर होगा महंगा !

भोपाल । मध्यप्रदेश में आने वाले समय में सडक से सफर करना महंगा हो सकता है। राज्य सरकार सडकों से होने वाली आय बढ़ाने के लिए टोल व्यवस्था का विस्तार करने की तैयारी में है। कम से कम 12 और सडकों को टोल के दायरे में लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य सडकों को भी भविष्य में इस व्यवस्था से जोडने की योजना है। फिलहाल प्रदेश में मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरडीसी) की अलग-अलग योजनाओं के तहत 93 सडकों पर 139 टोल प्लाजा संचालित हो रहे हैं। विभाग का मानना है कि नई सडकों को टोल व्यवस्था से जोडकर सरकार की आय में बड़ा इजाफा किया जा सकता है।अभी 400 करोड़, लक्ष्य 3 हजार करोड़ तक

पीडब्ल्यूडी से जुड़े अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के टोल से सालाना करीब 4 हजार करोड़ रुपये की आय होती है। इसके मुकाबले पीडब्ल्यूडी और एमपीआरडीसी की टोल से कमाई करीब 400 करोड़ रुपये सालाना है। इसी अंतर

को देखते हुए विभाग अगले 10 से 15 साल में टोल से होने वाली आय को बढ़ाकर 2 हजार से 3 हजार करोड़ रुपये सालाना तक पहुंचाना चाहता है।

इसके लिए नई सडकों का निर्माण टोल आधारित मॉडल पर करने पर जोर दिया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के अनुसार टोल आधारित नई सडकों से विभाग की आय बढ़ेगी। इससे सडक क्षेत्र में निवेश के साथ राज्य के राजस्व में भी विभाग का योगदान बढ़ाया जा सकेगा।

निजी कंपनियों के बजाय सरकार के पास आएगा टोल

सडक निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी अब हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी एचएएम को ज्यादा बढ़ावा देने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य यह भी है कि सडक बनने के बाद टोल से मिलने वाली राशि सरकार के पास आए। बीओटी मॉडल में सडक बनाने वाली निजी कंपनी निवेश करती है और तय अवधि तक टोल से अपनी लागत और मुनाफा वसूलती है। वहीं एचएएम में सडक निर्माण की लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा सरकार देती है, जबकि बाकी 60 प्रतिशत राशि निजी कंपनी लगाती है।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक और प्रकाशक शरद पाराशर द्वारा साईं प्रिंटर्स म.नं. 19 शॉप नं. 3 जिंसी पुलिस चौकी के पास जहांगीराबाद, भोपाल म.प्र.से मुद्रित करवाकर ए-52 कस्तूरबा नगर भोपाल से प्रकाशित।
संपादक- शरद पाराशर मो.9425023929, समाचार सम्पादक :-सेजल दीक्षित (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।)